● वर्ष-3
● अंक-250
रायपुर, बुधवार
29 मई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› आंवला- स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ..

भीषण गर्मी, प्रदेश में पारा 47 के पार

दिल्ली में तापमान 50 डिग्री पहुंचा

नई दिल्ली। उत्तर भारत समेत दिल्ली में प्रचंड गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मंगलवार को तो दिल्ली के मौसम विभाग के तीन केंद्रों पर तापमान 49 डिग्री से अधिक होने के कारण पचास डिग्री की तपिश महसूस हुई। मुंगेशपुर, व नरेला में तापमान 49.9 और नजफगढ़ में तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पूरी दिल्ली के मानक केंद्रो में सबसे अधिक रहा। जबकि दिल्ली के मानक केंद्र सफदरजंग में तापमान पांच डिग्री अधिक 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के 57 साल के इतिहास में पहली बार मंगलवार को आयानगर में और रिज में 51 साल में तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। आयानगर के 1967 से 2023 तक के तापमान के आंकड़े को देखें तो 28 मई 1988 को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री और 11 जून 2019 को तापमान 47 दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को आयानगर में तापमान ने छंलाग लगाई और 47.6 दर्ज किया गया। इस तरह से इस केंद्र का यह सबसे अधिक तापमान है। वहीं रिज में मंगलवार को तापमान 47.5 दर्ज किया गया। जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड बना। रिज के 1973 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार 16 मई 2022 को तापमान 47.2 और 7 जून 2014 को तापमान 46.3 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन तक ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी। बुधवार (29 मई) को भी गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

मुंगेली में पारा 47.3 दर्ज

नवतपा के तपन से पूरा प्रदेश झुलस रहा है. मंगलवार को मुंगेली में पारा 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी रायपुर में तापमान 45 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. लोगों को दिन में 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है. आज का दिन अब तक साल का सबसे गर्म दिन रहा. बिलासपुर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. गर्मी अपने चरम पर है. नवतपा के तपन से मुंगेली भी तप रहा, जहां पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है. लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. नगर के चौक-चौराहो पर सन्नाटा पसरा हुआ है. जरूरी कामकाज वाले लोग गला तर करते नजर आ रहे. भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस बार नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा।

मिजोरमः बारिश- भूस्खलनों के चलते 22 लोगों की मौत

मिजोरम में रेमल चक्रवात के प्रभाव के चलते मूसलाधार बारिश और भूस्खलनों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 13 की मृत्यु पत्थर खदान धंसने से हुई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मिजोरम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमएसडीएमए) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक भीषण भूस्खलन के कारण आइजोल जिले में पत्थर की खदान धंसने से दो नाबालिगों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य लापता हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी हिस्से में स्थित मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अब भी लापता हैं। पत्थर की खदान धंसने से मरने वालों मेंचार साल का लड़का और छह साल की लड़की शामिल हैं।

छठे चरण में 63.37% मतदान

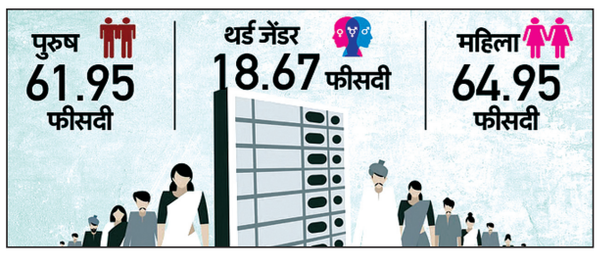

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के आखिरी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, छठे चरण में कुल मिलाकर 63.37% मतदान दर्ज किया गया। इसमें 61.95 फीसदी पुरुष, 64.95 फीसदी महिला और 18.67 फीसदी थर्ड जेंडर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 63.37 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 11.13 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 7.05 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के पहले छह चरणों में 87.54 करोड़ मतदाताओं में से 57.77 करोड़ मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग 96.88 करोड़ है।

चुनाव आयोग (ईसी) के अनुसार, 20 मई को हुए पांचवें चरण के मतदान में 62.2 प्रतिशत वोटिंग हुई। चौथे चरण में मतदान 69.16 प्रतिशत रहा, जो 2019 के आम चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65 प्रतिशत अधिक है।

तीसरे चरण में मतदान का आंकड़ा 65.68 फीसदी रहा। 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 फीसदी मतदान हुआ था। 2024 के चुनाव के दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा आम चुनाव के पहले चरण में 66.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43 फीसदी मतदान हुआ था।

दरअसल, लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 25 मई को आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें जम्मू-कश्मीर का अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र भी था, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हुआ।

राजग अबतक 370 सीट जीत चुका है-खट्टर

गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव के लिए अबतक हुए छह चरणमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 360 से 370 सीट जीत चुका है और सातवें चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े को पार कर लेगा।

पंचकूला में पार्टी की बैठक के बाद यहां भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खट्टर ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीट जीतेगी और नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक हुए छह चरणों के चुनाव में राजग 360-370 सीट जुकी है।

''अब सातवें चरण का चुनाव पूरा होते ही हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी।'' उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत का क्रम बरकरार रखेगी। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस पूरे चुनाव में घबराई हुई नजर आई और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण होगा। हरियाणा सरकार की स्थिरता के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के पास बहुमत है और वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। खट्टर ने कहा, '' हमारे पास 88 (हरियाणा विधानसभा में मौजूदा कुल विधायकों की संख्या) में से 45 विधायक हैं और हमारी सरकार बहुमत में है। हमारे समर्थन में दो जजपा, एक हलोपा (हरियाणा लोकहित पार्टी) और तीन निर्दलीय विधायक हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। राज्य में भाजपा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।'' उन्होंने हरियाणा में 25 मई को हुए मतदान के दौरान कथित फर्जी मतदान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोहतक और सिरसा के अलावा एक - दो और जिलों में फर्जी मतदान के मामले सामने आए हैं। यदि कोई (राज्य सरकार का) कर्मी फर्जी मतदान में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

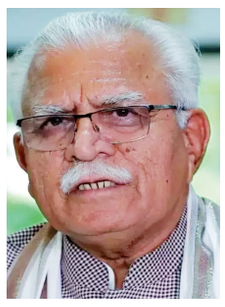

अब 'गाली प्रुफ' हो गया हूंः मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 24 साल से गाली खा-खाकर गाली प्रुफ हो गया हूं। चुनाव के दौरान निजी टिप्पणियों को लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था। मेरे यहां तो संसद के एक साथी ने हिसाब लगाया और 101 गालियां गिनाईं। चुनाव हो या ना हो। ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का अधिकार उनका ही है। वे हताश-निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनके स्वाभाव में हो गया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने रातों-रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी के दौरान हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया , तब साफ हुआ कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अब वे न्यायपालिका को भी गाली दे रहे हैं। वे यहां तक कह रहे हैं कि हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। यह स्थिति किसी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी। प्रधानमंत्री से जब विपक्ष के ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, विपक्ष ने आपको कूड़ा कचरा पकड़ा दिया। वह कूड़ा कचरा लेकर आप हमारे पास पहुंच गए। मीडिया वाले रिसर्च करें कि सरकार से क्या सवाल पूछने चाहिए। उनका कूड़ा कचरा लेकर आप हमारे यहां आते हैं। मैं कूड़े कचरे को रीसाइकल करके खाद में परिवर्तित कर दूंगा।

मोदी फिर होंगे ध्यान में लीन कन्याकुमारी का करेंगे दौरा

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे, जो उनके लोकसभा चुनाव अभियान की समाप्ति होगी। प्रधान मंत्री मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे, वही स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। यह स्थान महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व रखता है, जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण है। कन्याकुमारी उस स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है जहां स्वामी विवेकानन्द को तीन दिनों तक ध्यान करने के बाद भारत माता के दर्शन हुए थे। इसके अतिरिक्त, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा करते हुए यहां एक पैर पर ध्यान लगाया था। भारत का यह सबसे दक्षिणी छोर वह स्थान भी है जहाँ पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएँ मिलती हैं, और जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं।

प्रमुख समाचार

बेमेतरा ब्लॉस्ट की दंडाधिकारी जांच 4 बिंदुओं पर हुई शुरू

बेमेतरा/रायपुर। बारुद फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लॉस्ट में मरने वालों की सही संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है। मौके से जब्त किए गए शवों के टुकड़ों की डीएनए जांच कराने की तैयारी है। इस बीच पूरे मामले की मजिस्ट्रिलय जांच शुरू हो गई है। जिले की एसडीएम पिंकी मनहर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बारुद फैक्ट्री में हुए ब्लॉक की न्यायिक जांच के लिए सरकार ने 4 बिंदु तय किए हैं। एसडीएम अपनी जांच रिपोर्ट में सबसे पहले दुर्घटना के कारणों की पड़ताल करेगीं। जांच का दूसरा बिंदु फैक्ट्री के लाइसेंस और वहां सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल से जुड़ा है। इसमें यह जांच की जाएगी कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा वहां किए गए सुरक्षात्मक उपायों का परीक्षण, अनुज्ञप्ति, भंडारण उपयोग की स्थिति क्या थी। जांच का तीसरा बिंदु जिम्मेदारी तय करने वाला है। इसमें दुर्घटना विस्फोट के लिए यदि कोई त्रुटि लापरवाही है, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण। अन्य कोई सुझाव या बिंदु जो जांच अधिकारी सम्मिलित करना आवश्यक समझें। बता दें कि बेरला ब्लाक के ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में 25 मई को सुबह ब्लास्ट हो गया था। घटना में अब तक केवल एक व्यक्ति के मरने और दर्जभर के घायल होने की सूचना है।

गुरमीत राम रहीम हत्या के केस में बरी, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रणजीत सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने चार अन्य आरोपियों को भी बरी किया है। इस हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 को सिरसा डेरे के प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच 2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी। जिस पर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार किया था।

पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलनः जिंदा दफन हो गए 2 हजार लोग

नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को पापुआ न्यू गिनी के लिए 1 मिलियन डॉलर की तत्काल सहायता राशि की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी में पिछले शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2,000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं। इस भीषण हादसे के बाद वहां की सरकार ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है जिसके बाद भारत ने सहायता राशि की घोषणा की है। 24 मई की सुबह हुए भूस्खलन से इलाके में भारी तबाही देखी गई है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से 600 किमी उत्तर-पश्चिम में भूस्खलन की यह घटना हुई है। कुछ स्थानों पर उपकरणों की कमी के कारण जीवित बचे लोगों को बचाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत एक करीबी दोस्त और भागीदार के रूप में हम पापुआ न्यू गिनी के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। भारत सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण लोगों की मौत और तबाही होने पर मंगलवार को दुख जताया।

बस्तर में बारूद बिछाकर रखना पूरी तरह से अनुचित है: शर्मा

रायपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के थाना जगरगुंडा अंतर्गत ग्राम भीमापुरम से मड़कम सुक्की नामक युवती का आईईडी ब्लास्ट से पैर बुरी तरह चोटग्रस्त हो गया है। ब्लास्ट में घायल युवती को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। डॉक्टर्स ने तत्काल उपचार मिलने के बाद युवती की जान बच जाने की उम्मीद जताई है।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ऐसी ही घटना बीजापुर जिले के अन्नू नेकाम के साथ भी घटी थी। अन्नू नेकाम का पैर आईईडी ब्लास्ट में अलग हो गया था उसका भी रायपुर लाकर रामकृष्ण हॉस्पिटल में उपचार किया गया था। बीजापुर में ही आईईडी ब्लास्ट से दो श्रमिकों व दो बच्चों की मौत हुई थी। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में भी एक ग्रामीण की ब्लास्ट से दुखद मृत्यु हुई थी। वहीं 11 मई को बीजापुर में एक युवती आईईडी की चपेट में आई थी। श्री शर्मा ने कहा कि आईईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या फिर जानवर हैं, या फिर यह नक्सली है या फिर यह आम नागरिक हैं।

सीबीआई ने शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच जनवरी को संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के संबंध में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख, उसके भाई और पांच अन्य पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में एजेंसी का पहला आरोपपत्र सोमवार को बशीरहाट विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि टीम शेख को गिरफ्तार करने भी गई थी क्योंकि घोटाले में जांच के घेरे में आए, गिरफ्तार पूर्व राज्य खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के साथ उसके कथित करीबी संबंध थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में सात लोगों के नाम हैं, जिनमें शेख, उसका भाई आलमगीर और सहयोगी जियाउद्दीन मुल्ला, मफुजर मुल्ला और दीदारबख्श मुल्ला शामिल हैं।

क्या प्यार, युद्ध और चुनाव में हर झूठ, प्रपंच जायज है?

संजय तिवारी

अब जबकि लोकसभा की लगभग 485 सीटों पर मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है तब अंतिम चरण की ओर बढता यह आम चुनाव अपनी एक छाप पीछे छोड़ते हुए जा रहा है। वह छाप है कि इस आम चुनाव ने साबित किया है कि राजनीति में नैतिकता का जो अकाल था अब वो घोर दुष्काल में बदल गया है। वास्तविक मुद्दों से दूर नेता झूठ, प्रपंच और पाखंड का सहारा लेकर अपने ही देश के मतदाताओं से छल करने में जरा भी नहीं चूकते। उनके आदर्शवादी व्यवहार का उपदेश सिर्फ सत्ता में आने के बाद भाषणों में बोलने के लिए रह गये हैं। चुनावी मैदान में वो मानकर चलते हैं कि वो कोई भी छल प्रपंच करके जनता को भरमाने के लिए स्वतंत्र हैं।

2014 में राष्ट्रीय क्षितिज पर नरेन्द्र मोदी का उदय हुआ था उस समय नेताओं की विश्वसनीयता रसातल में थी। कांग्रेस के दस साल के शासन में भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे थे कि मेरा नेता चोर है एक सामान्य सा जुमला बन गया था। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन ने नेताओं की इस विश्वसनीयता को और गिराने का ही काम किया था। अगर उसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर नरेन्द्र मोदी का उदय न हुआ होता तो यह संभव है कि 2014 का आम चुनाव वोटिंग के लिहाज से अब तक का सबसे कम मतदान वाला चुनाव साबित होता।

लेकिन नरेन्द्र मोदी के उभार ने पूरे देश के लोगों तक यह संदेश दिया कि एक नेता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वह भ्रष्ट नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई परिवार नहीं है। नरेन्द्र मोदी के हिन्दुत्ववादी होने से अधिक जन सामान्य में उनकी छवि एक ऐसे विकास पुरुष की बनी जिसने गुजरात को लंदन, पेरिस बना दिया है। पहली बार सोशल मीडिया का चुनाव में इतना व्यापक इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया के जरिए नरेन्द्र मोदी की पीआर एजंसी ने ब्रांड मोदी के प्रति एक ऐसा विश्वास पैदा किया जो शेर जैसा बहादुर है, निडर है और एक गरीब चायवाले का बेटा होकर भी भ्रष्ट नहीं है।

कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उकताये जन सामान्य में मोदी को एक ऐसा %अवतार% नजर आया जो उनके दुख, गरीबी और कष्टों से राहत देकर देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। उस चुनाव प्रचार ने अधिकांश लोगों के मन में यह बात स्वतः ही बिठा दी कि मोदी आयेंगे तो इंडिया को सुपर पॉवर बना देंगे। हालांकि सोशल मीडिया का ये समूचा कैम्पेन एक पीआर कैम्पेन था और पहली बार डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए सच को झूठ के साथ कुछ इस तरह मिलाया गया था कि सच तक पहुंच पाना किसी आम व्यक्ति के लिए असंभव था। इसलिए वह सब सच मान लिया गया जो असल में झूठ था।

अपनी शुरुआत के पांच सात साल के छोटे से इतिहास में ही 2013-14 में पहली बार सोशल मीडिया इतना बुरी तरह बंटा था कि जोड़ने का काम करनेवाला फेसबुक लोगों को तोड़ने का जरिया बन गया। इतना गहरा पोलिटिकल डिवाइड इससे पहले कब हुआ था, यह तो पता नहीं लेकिन इस बंटवारे का असली कारण चुनाव जीतने के लिए फैलाये गये कुछ ऐसे झूठ थे जिसे कांग्रेस काउण्टर करने की स्थिति में ही नहीं थी। मोदी चुनाव जीत गये। भाजपा को अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला और नरेन्द्र मोदी संपूर्ण सम्मान और उत्साह के साथ देश के प्रधानमंत्री बन गये।

हालांकि मोदी के दस साल के शासनकाल को देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो जितने आक्रामक, सतही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शासन के दौरान उन्होंने उतना ही संयम रखा और ऐसा कुछ भी करने से परहेज किया जिससे उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़े। संभवतः मोदी यह मानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार में आने के बाद वही सब करने भी लगे।

लेकिन समस्या यह हो गयी कि एक बार चुनाव जीतने के लिए अगर सतही भाषा, छद्म तरीकों का इस्तेमाल शुरु हो जाए तो गिरती राजनीति को वह और अधिक रसातल में ही ले जाता है। 2014 और 2019 का आम चुनाव हो या उसके पहले गुजरात का विधानसभा चुनाव। मोदी और कांग्रेस में हमेशा एक होड़ दिखाई दी कि कौन किसके खिलाफ कितनी सतही और गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है। मोदी को मौत का सौदागर और नीच आदमी तक कहा गया जिसका मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया और चुनावों में बंपर जीत हासिल की।

यहां एक बात और गौर करने लायक है। मोदी ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो संभव है वो 2009 वाले आडवाणी बनकर रह जाते। हमेशा के लिए पीएम इन वेटिंग। यह मोदी की आक्रामक शैली का ही परिणाम था कि ऑक्टोपस की तरह कहीं से भी प्रहार करने में माहिर कांग्रेस गुजरात के एक मुख्यमंत्री के सामने धराशायी हो गयी। इसलिए मोदी ने अगर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया तो यह एक बड़े वर्ग को बुरा नहीं लगा। मोदी की अपनी राजनीतिक शैली ऐसी है कि सत्ता संचालन में जितने सधे हुए और संयमित रहते हैं, चुनाव प्रचार में उतरते ही उतने ही बिखरे हुए और असंयमित हो जाते हैं। वो विपक्ष को लेकर बड़ा से बड़ा झूठा आरोप लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते।

1 लाख के ईनामी नक्सली सहित 3 गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन के तहत नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला बल एवं डीआरजी सुकमा की संयुक्त पार्टी नक्सलियों के कोर एरिया ग्राम जबेली, रासातोंग, सिंगाराम व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान रासातोंग से जबेली जाने वाले के पकडंडी रास्ते के पास से घेराबंदी कर 2 नक्सलियों कवासी पोज्जा पिता कवासी भीमा (सिंगाराम आरपीसी सीएनएम कमाण्डर, ईनाम 01 लाख रूपये) एवं ताती उर्फ मड़कम पोज्जा पिता स्व. मड़कम गंगा (सिंगाराम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर) दोनो निवासी जबेली थाना गोलापल्ली जिला सुकमा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 नग टिफिन बम लगभग 2 किग्रा. 5 नग जिलेटिन रॉड, 5 नग डेटोनेटर, 20 मीटर लगभग बिजली वायर, 2 फीट कोर्डेक्स वायर बरामद किया गया। उक्त बरामद विस्फोटक सामाग्री को रखे जाने के संबंध में पूछने पर बड़े नक्सली एलओएस कमाण्डर सोड़ी जोगा के कहने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रखना बताये। उक्त कृत्य विधि विरूद्ध पाये जाने से दोनों नक्सलियों के खिलाफ थाना गोलापल्ली में अपराध क्रमांक 02/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही के उपरांत आज मंगलवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दखिल किया गया।

इसी क्रम में थाना गोलापल्ली से जिला बल व 18 वीं वाहिनी छसबल की सयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन/नक्सली आरोपियों की धरपकड़ हेतु ग्राम पुजारीपारा व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान ग्राम पुजारीपारा जंगल के पास से एक महिला नक्सली तुरसा एंका पिता तुरसा चंद्रा (सिंगाराम आरपीसी मिलिशिया सदस्य) निवासी पुजारीपारा गोलापल्ली को गिरफ्तार कर थाना लाकर नक्सल रिकार्ड जांच करने पर तुरसा एंका थाना गोलापल्ली क्षेत्रान्तर्गत 16 अगस्त 2022 को तारलागुड़ा-किस्टाराम के मध्य रोड़ खोदने एवं सुरक्षाबलों पर फायरिंग करने की वारदात में अन्य नक्सलियों के साथ शामिल रहना पाया गया, घटना के संबंध में थाना गोलापल्ली में अपराध क्रमांक 01/2022 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि. 03 लोक सम्पति निवारण अधिनियम, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण में तुरसा एंका के विरूद्ध कार्यवाही उपरांत आज मंगलवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल दाखिल किया गया।

आईईडी विस्फोट में घायल महिला के इलाज के लिए भेजा गया रायपुर

सुकमा। जिले के नक्सल प्रभावित भीमापुरम में नक्सलियों के द्वारा एक ग्रामीण के घर में जबरन आईईडी रखवा दिया था, रविवार को घर में अईईडी में विस्फोट होने से 02 ग्रामीण महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। विस्फोट में एक महिला के पैर के चीथड़े उड़ गए। अब उस घायल महिला मड़कम सुक्की को रायपुर भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घर में आईईडी विस्फोट के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले में गंभीरता लेते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घायल महिला को घोर नक्सल प्रभावित भीमापुरम से बाहर निकलवाया। घायल महिला मड़कम सुक्की को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। घायल मड़कम सुक्की का पैर बुरी तरह से आईईडी विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ था। महिला को रायपुर तक ले जाने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को महिला के साथ भेजा गया।

गोगुंडा की पहाड़ी में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में भागे नक्सली

सुकमा। गोगुंडा की पहाड़ी में मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोगुंडा की पहाड़ी पर नक्सली कमांडर जगदीश समेत भारी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर सुकमा से डीआरजी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। जवान जब इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए, मुठभेड़ रुकने के बाद जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित हैं। नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, जवान जब लौटेंगे तब पता चल पाएगा।

पकड़े गए 15 नक्सली

दंतेवाड़ा। गुमलनार के गिरसापारा की पहाड़ियों पर गश्त में निकले जवानों ने 15 नक्सलियों को बम ब्लास्ट कर भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से आईईडी बम, पिट्ठू बैग, नक्सली वर्दी, सब्बल, फावड़ा, दैनिक उपयोग के समान जब्त किए गए।

सड़क बनाने किसानों की जमीन अधिग्रहित मुआवजा मांगने पर धमका रहे अधिकारी

■ मियाद खत्म होने के बाद भी नहीं बनी सड़क

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सड़क बनाने वाली कंपनी एडीबी की मनमानी देखने को मिल रही है। जिले में सड़क निर्माण के लिए सालों पहले किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। मुआवजे की मांग करने पर अधिकारी प्रशासन की मदद से किसानों को धमका रहे हैं।

वहीं समय सीमा खत्म होने और सालों बीतने के बाद अब तक सड़क बनकर तैयार नहीं हो पाई है। अब आगामी बरसात को देखते हुए एडीबी नियम विरुद्ध जा कर सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। एडीबी की मनमानी और मुआवजे ना मिलने को लेकर किसानों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश उभरने लगा है।

दरअसल, सालों पहले जिले में सक्ती से टुंडरी मार्ग पर लम्बाई 31-481 कि. मी. और मालखरौदा से जैजैपुर मार्ग के सड़क निर्माण और चौड़िकरण के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। जिसमें सक्ती-टुन्ड्री मार्ग के लिए अतिरिक्त जमीन क्रय निति शासन का आदेश क्रमांक एफ 7-4-1/20215 दिनांक 30 मार्च 2016 का संशोधन दिनांक 27-09-2017 के अनुसार ग्राम कर्रापाली एवं झर्रा के किसानों को मुआवजा दिया गया।

इनमें से बहुत से किसानों ने मुआवजा राशी पर सहमती नहीं दी थी। जिसके बाद उनके जमीनों का फिर से नाप हुआ और राजस्व विभाग द्वारा जमीन का प्रकरण बनाया गया। लेकिन आज तक उन बचे हुए किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। किसान लगातार साल 2021 से शासन-प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, इन दोनों मार्गों पर सड़क बनाने के लिए 16 मीटर चौड़ी जमीन की आवश्यकता थी, लेकिन कई जगहों पर किसान मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण एडीबी के साथ उन किसानों का समझौता नहीं हो सका। उन जगहों पर अब एडीबी के अधिकारी नियम विरुद्ध सड़क बना रहे हैं। कई जगहों पर 12 मीटर तो कही 10 मीटर तो कही 8 मीटर सड़क बनाने की तैयारी चल रही है। जबकि सड़क निर्माण के लिए पहले से ही एस्टीमेट तैयार हो चुका है, लेकिन अब एडीबी द्वारा एस्टीमेट से हटकर कार्य कराया जा रहा है जो की नियम विरुद्ध है। इस मामले में राजस्व अधिकारी का कहना है, की कुछ किसानों से सहमति नहीं बन पाई है, मगर बरसात को देखते हुए वहां पूर्व की शासकीय सड़क पर ही सड़क निर्माण कराया जाएगा। बाद में किसानों से अगर सहमति बनती है, तो सड़क और चौड़ी कर देंगे।

जमीन का फर्जीवाड़ा, सरकारी कर्मियों सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

जांजगीर। दूसरे की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम चढ़ाकर बेच देने के मामले में उप पंजीयक, दो तहसीलदार और तीन पटवारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार बेलसरी, तखतपुर के संजय कुमार पांडेय (47 वर्ष) ने चांपा के समीप ग्राम कुरदा में निरंजन पांडेय से 15 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसका नामांतरण कराने के बाद उसने ऋण पुस्तिका भी तैयार कर ली थी। कुछ समय बाद उसे जानकारी मिली कि उसकी जमीन साहिल राज देवांगन के पास 15 लाख रुपये में बेची जा चुकी है। जमीन के मालिक ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कुरदा के संजय कुमार बरेठ नाम के व्यक्ति ने राजस्व व पंजीयन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की बिक्री की है। आरोप के मुताबिक तत्कालीन पटवारी अरविंद साहू व तहसीलदार डीएस उइके की मदद से उसने फर्जी ऋण पुस्तिका और बी-1 खसरा तैयार करा लिया। भूमि की बिक्री के लिए पंचनामा और चौहद्दी का आदेश उसने तत्कालीन तहसीलदार सरस्वती बंजारे से प्राप्त कर लिया और एक अन्य पटवारी भूषण मरकाम से साठगांठ कर पंचनामा व फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिया। इसमें दो गवाह संतोष देवांगन और अभय पांडेय के जरिये अपने को जमीन का मालिक प्रमाणित करा लिया और फिर जमीन बेच दी।

जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचे जाने की जानकारी

मिलने पर संजय पांडेय ने चांपा थाने में तथा पुलिस अधिकारियों को शिकायत की लेकिन संजय बरेठ और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अदालत में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चांपा थाने में विक्रेता संजय कुमार बरेठ, खरीददार साहिल देवांगन, गवाह संतोष देवांगन व अभय पांडेय, पटवारी अरविंद साहू, पटवारी युवराज पटेल, पटवारी भूषण मरकाम, चांपा के तत्कालीन तहसीलदार रहे डीएस उईके और तहसीलदार सरस्वती बंजारे, चांपा के उप पंजीयक रहे विजय कुमार दिडतुडुक के खिलाफ धारा 120 बी, 34, 467, 468, 469, 471 के तहत चांपा थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बैंक मैनेजर ने ही रची थी लूट की साजिश

राजनांदगांव। नेशनल हाईवे चिचोला में सोमवार को एक पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ कथित रूप से हुए लूटपाट की घटना का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। मैनेजर ने ही अपने दोस्तों के साथ लूट की साजिश रची थी। लाखों रुपए देखकर मैनेजर की नियत डोल गई और उसने दो दोस्तों को लूट की साजिश में शामिल कर लिया। नेशनल हाईवे में हुए इस वारदात को लेकर पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी करते हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोत के जरिये पुलिस ने लूट के मास्टर माईंड मैनेजर और उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक घोरतालाव स्थित मारूति फ्यूल्स का मैनेजर राजाराम विश्नोई पंप से 14 लाख रुपए लेकर बाइक से राजनांदगांव जाने निकला था। इस दौरान तथाकथित रूप से मैनेजर के साथ तेन्दूनाला के पास लूटपाट की वारदात हुई। हाईवे में हुए लूट की वारदात को पुलिस ने गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की। मैनेजर ने लुटेरों को कार में आने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नेशनल हाईवे समेत अन्य प्रमुख रास्तों में नाकेबंदी कर दी। आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से 13 लाख 24 हजार रुपए बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को मैनेजर वारदात को लेकर गोलमोल जवाब दे रहा था। पुलिस को घटनास्थल तक मैनेजर के पेट्रोल पंप से निकलने पर लिए लंबे वक्त को लेकर शक हुआ। मैनेजर ने अपने साथियों से धारदार हथियार से खुद पर हमला भी करवाया। सूत्रों का कहना है कि मैनेजर ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। लूट में प्रयुक्त कार को लेकर भी मैनेजर द्वारा गलत जानकारी दी गई। मैनेजर ने दो आरोपियों के ब्लेजर कार में आने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस को कहीं भी उक्त कार का पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने एक स्वीफ्ट कार को बरामद किया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

12 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के समर्थन में बंद रहा बस्तर

सर्व आदिवासी समाज ने किया था बंद का एलान

जगदलपुर। बीजापुर जिले के ग्राम पीडिया में 10 मई को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा फर्जी बताने के साथ ही उस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही बस्तर बंद का आव्हान किया गया। जिसपर मंगलवार को दुकानदारों से लेकर व्यापारियों ने अपना समर्थन देने के साथ ही अपनी दुकानों को बंद रखा इस दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया था।

बताया जा रहा है कि बीजापुर जिले के ग्राम पीडिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच मे मुठभेड़ हुई थी जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मारागुमेड तेंदूपत्ता खरीदी फंड में ग्रामीण तेंदूपत्ता खरीदने तो कुछ बेचने के लिए गए हुए थे। अचानक से पुलिस टीम को आता देख ग्रामीण डर के चलते भाग खड़े हुए, पुलिस की टीम ने चारों ओर से ग्रामीणों को घेर लिया, कुछ ग्रामीण पेड़ में चढ़ गए तो कुछ लोग झाड़ियों के पीछे छुप गए।

कहा जा रहा है कि ग्रामीणों के खुद साधारण ग्रामीण बताने के बाद भी पुलिस टीम ने ग्रामीणों को गोली मारी, जिसके बाद इसी मामले की जांच को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को नगर बंद कराया। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर अन्य कुछ पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

डोंगरगढ नपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

डोंगरगढ़। डोंगरगढ नपा अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अध्यक्ष से नाराज चल रहे कांग्रेसी पार्षदों ने कथित रूप से भाजपा पार्षदों के साथ हाथ मिला लिया है। नगर पालिका के 14 पार्षदों ने अध्यक्ष को हटाने के लिए कलेक्टर को पत्र सौंपा है। अगले 10 दिनों में नगर पालिका की कुर्सी को लेकर काफी उठापटक रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर के समक्ष भाजपा के 14 पार्षदों ने धारा 43 (क) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 2019 का हवाला देते क्षेत्र में 6 बुनियादी समस्याओं को गिनाते इस अविश्वास प्रस्ताव लाया है। भाजपा पार्षदों की माने तो पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम द्वारा साढ़े 4 साल के शासनकाल में कमीशनखोरी को चरम पर रखा गया। पार्षद ने कलेक्टर को दिए पत्र में शहर के स्वच्छता अभियान पर भी सवाल किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से कलेक्टर को बताया कि अध्यक्ष के नाकामी के कारण ही पालिका में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के खाते में किस्त डालने में भी पक्षपाती रूप अपनाया गया।

नवतपा के चौथे दिन 46 डिग्री पहुंचा पारा

बिलासपुर। नवतपा के तपन पर पूरा छत्तीसगढ़ तप रहा है। आज का पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने लू आ अलर्ट जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दिन में 12 से 4 बजे तक घर से न निकलने की हिदायत दी है। आज का दिन अब तक साल का सबसे गर्म दिन रहा। बिलासपुर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी अपने चरम पर है। नवतपा के तपन से मुंगेली भी तप रहा। यहां पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नगर के चौक-चौराहो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जरूरी कामकाज वाले लोग गला तर करते नजर आ रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है।

रेत के अवैध भंडारण पर खनिज विभाग की कार्रवाई

बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर ने ग्राम जोंधरा तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भंडारण का मौका जांच किया। जिसमें अशोक कर्ष निवासी अकलतरा के पास लगभग 120 हाईवा/1440 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया। इसी तरह मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के प्रो। जितेंद्र सिंह को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाईवा/2400 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया। खनिकर्म विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रकरणों में मौके पर रेत भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी दस्तावेज और भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान और खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 छत्तीसगढ़ खनिज(खनन,परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जब्त कर अवैध भंडारणकर्ता को 03 कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

वंदेभारत में तकनीकी खराबी निपनिया में खड़ी रही ढाई घंटे

बिलासपुर। नागपुर-बिलासपुर वंदेभारत एक्सप्रेस में खराबी आ जाने से कल शाम ढाई घंटे तक निपनिया में रुकी रही। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन में आई तकनीकी दिक्कत दूर की जा सकी और यात्रियों को बिलासपुर पहुंचाया गया। इस बीच ट्रेन की बिजली और एसी बंद हो गई थी, गर्मी से बेहाल यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। नागपुर से बिलासपुर के लिए 27 मई को यह ट्रेन समय पर रवाना हुई थी लेकिन भाटापारा से बिलासपुर के बीच निपनिया में अचानक यह ट्रेन ठहर गई। अमूमन यह ट्रेन रायपुर बिलासपुर के बीच कहीं पर भी नहीं रुकती। यात्रियों को कुछ देर तक लगा कि रेड सिग्नल की वजह से ट्रेन रुकी है। मगर, थोड़ी ही देर में ट्रेन से बिजली चली गई और एसी भी बंद हो गया। यात्रियों को समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन में खराबी आ गई है। ट्रेन के पायलट ने ट्रेन के तकनीकी कारण से रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम में दी। इसके बाद भाटापारा से टेक्निकल टीम आई। उसने काफी मशक्कत के बाद खराबी का पता लगाया। पता चला कि ओएचई तार में ट्रेन का पेंटो फंस गया था।

शादी में शामिल होने आया आरोपी, दुर्ग पुलिस ने दबोचा

दुर्ग। मोहन नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने भाई की शादी में शामिल होने दुर्ग पहुंचा था। पुलिस सूचना पाते ही शादी के मंडप में पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने शादी के मंडप से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने भाई के शादी कार्यक्रम में पहुंचा था। तभी पुलिस को आरोपी की मुखबिर से सूचना मिली। जहां हल्दी के रस्म के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पिछले 6 सालों से आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। जिस वक्त पुलिस आरोपी को पकड़ कर अपने साथ थाना लेकर आई। उस दौरान भी उसके शरीर में हल्दी लगा हुआ था। दरअसल, दुर्ग पुलिस इन दिनों फरार वारंटी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी का न्यायालय से वारंट जारी हुआ है। जिस संबंध में आरोपी की पतासाजी लगातार की जा रही थी।

किसानों के लिए बनीं नहर भ्रष्टाचार की शिकार

■ गुणवत्ता से हुआ समझौता, अफसर हैं मौन

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलका में करीब एक करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से जल संसाधन विभाग ठेकेदारी प्रथा के आधार पर नहर का निर्माण करवा रहा है। इस नहर का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना था।लेकिन निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता किया गया।जिसका असर ये हुआ कि मौजूदा समय में नहर की दीवारों में दरार आ गई है।

वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जल संसाधन विभाग के जिला मुख्य कार्यपालन अभियंता को दी गई।जिसके बाद उन्होने कहा कि ठेकेदार को नहर

निर्माण में जो भी कमी है उसे सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि निर्माण के समय ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकलते तो नहर की ये दुर्दशा नहीं होती।वहीं इस बारे में जब निर्माण कार्य के दौरान मौजूद मुंशी से निरीक्षण पंजी और इस्टिमेट मांगा गया तो उनके पास नहीं मिला।

आपको बता दें कि एमसीबी जिले में जल संसाधन विभाग 1 करोड़ 80 लाख की लागत से नहर बनवा रहा है।जिसके लिए ग्राम पंचायत सलका में काम हो रहा है।लेकिन इस निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से कई तरह की अनियमितताएं देखी गई। जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार आनन-फानन में नगर का काम करवाकर सिर्फ बिल निकलवाना चाहता है।ना तो उसे किसानों से कुछ लेना है और ना ही शासन की योजना से।उसे सिर्फ अपना फायदा निकालकर जैसे तैसे नहर का निर्माण कार्य कर देना है।

महासमुंद शासकीय मेडिकल कॉलेज पर लाखों का जुर्माना

महासमुंद। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ी खबर मंगलवार को सामने आई है। यहां नेशनल मेडिकल काउंसिल, एनएमसी ने महासमुंद के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर बड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माने की कार्रवाई की है। ऑनलाइन निरीक्षण के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह कार्रवाई की है। ऑनलाइन इंस्पेक्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज में कई तरह की खामियां पाई गई थी जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज को चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में दो महीने के भीतर कमियों को पूरा करने की बात कही गई है। महासमुंद के गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज को साल 2022 में 125 सीट की मान्यता मिली थी। इसके बाद से अब तक 250 छात्र छात्राएं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। जब ऑनलाइन इंस्पेक्शन हुआ तो यहां टीचरों की कमी पाई गई। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। यह निरीक्षण की कार्रवाई 11 मई को की गई थी।

कोरबा में 36 घंटे से बिजली गुल, मोर्चा खोल धरने पर बैठे लोग, पार्षद भी संग

कोरबा। प्रदेश के साथ ही कोरबा में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कोरबा जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। हालात इस कदर गंभीर हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर के बीच धनवार पारा में पिछले 36 घंटे से बिजली नहीं है।

गर्मी से परेशान धनवार पारा के लोग बीती रात तुलसीनगर स्थित विद्युत वितरण विभाग के मुख्य कार्यालय पहुंच गए। मौके पर ही धरना देकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धनवार पारा वही क्षेत्र हैं, जहां प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर और पूर्व महापौर जोगेश लांबा रहते हैं। लोगों के प्रदर्शन से वितरण कंपनी के अधिकारियों के हांथ पांव फूल गए।

भाजपा पार्षद धनेश्वरी साहू के नेतृत्व में बैठे

लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से बिजली विभाग बिजली कटौती के नाम से लाइट गुल कर रही है। जिससे आम जनता काफी परेशान है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं बिजली नहीं होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे गर्मी में रहने को मजबूर हैं।

इस तेज गर्मी में बिना पंखे और कूलर के रहना बड़ा मुश्किल है। इसकी शिकार संबंधित विभाग से करने के बावजूद भी वह अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फोन करने पर ना ही फोन उठाते हैं। मजबूरन उन्हें विद्युत विभाग का घेराव करना पड़ा।

संक्षिप्त समाचार

शूटरों के गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर पुलिस की थपथपाई पीठ

रायपुर। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो बड़े कारोबारियों को मारने आए लॉरेंस और अमन गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक बहुत बड़े षड़यंत्र का पर्दाफाश किया है। जिससे कि राजधानी रायपुर में होने वाली एक बड़ी अनहोनी टल गई। उन्होंने ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम बधाई देना चाहेंगे हमारे पुलिस के जवानों को, जिन्होंने एक अनहोनी घटना घटने वाली थी। उसको समय रहते पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार आई है, तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। सीएम विष्णुदेव ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई-अमन साहू गैंग के चार शूटर छत्तीसगढ़ को दहलाने की नापाक साजिश कर रहे थे। जिसे रायपुर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या करने की सुपारी मिली थी। जिसका समय रहते रायपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया।

वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें किया नमन

रायपुर। महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने सावरकर की जीवन गाथा को समस्त भारतीयों के लिए प्रेरणादायक बताया। साथ ही सीएम साय ने जयंती पर एक वीडियो संदेश दिया है। मुख्यमंत्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि- मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के वासियों, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी को आज उनकी जयंती पर शत-शत् नमन। उन्होंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी वीर सावरकर की आज जयंती है। उन्होंने भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की अलख जगाई।

आइजोल में पत्थर खदान के ढहने से 13 की मौत, मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में पत्थर खदान के ढहने से 13 लोगों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया एकाउंड एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में पत्थर खदान के ढहने से 13 लोगों के निधन की दुखद खबर मिली है। हादसे में कई लोग लापता हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और लापता लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ।

छत्तीसगढ़ 2047 विजन डाक्यूमेंट संबंधी स्टेयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न

रायपुर। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047

डाक्यूमेंट के लिए गठित स्टेयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक की संपन्न हुई। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता और मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सह अध्यक्षता में राज्य नीति आयोग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ 2047 विजन डाक्यूमेंट तैयार किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में विभागों के प्रमुख अधिकारियों को विजन डाक्यूमेंट तैयार करने और तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव धर्मस्व विभाग सुब्रत साहू, गृह एवं जेल मनोज पिंगुआ और वन एवं जलवायु परिवर्तन ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिवद्वय पी दयानंद और बसवराजू एस सहित सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग के सलाहकार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

6 स्थानों के आहाता व्यवस्थापन के लिए खुली निविदा

रायपुर। रायपुर जिले के आबकारी विभाग का आहाता व्यवस्थापन का निविदा मंगलवार को खोला गया। 6 दुकानों के लिए द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके लिए कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त निविदादाता अर्हत पाए गए। निविदा खोलने के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उपायुक्त आबकारी श्री विकास गोस्वामी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री वैभव मितताल, श्री आशीष सिंह, श्री डीडी पटेल व निविदादाता उपस्थित थे। उपल्लेखनीय है कि 10 मई 2024 को प्रथम निविदा में रायपुर जिले की 56 आहातों के विरूद्ध 50 में लाइसेंस फीस व सुरक्षा निधि जमा की गई। द्वितीय निविदा के लिए आज 6 आहातों के लिए फिर निविदा खोला गया।

इतिहास में ब्राम्हण समाज का योगदान वंदनीय: बृजमोहन

ब्राम्हण समाज के 127 प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित

रायपुर। सरयूपारीण ब्राम्हण समाज के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होने दसवीं व बारहवीं बोर्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है आज तुलभी भवन में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सम्मानित किया और कहा कि देश के इतिहास में ब्राम्हण समाज का योगदान वंदनीय रहा है। मेधावी बच्चों से आग्रह किया कि समाज संत महापुरूषों का अनुसरण करते हुए वे निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो लेकिन समाज के प्रति अपने दायित्वों को कभी न भूलें।

इस बीच अग्रवाल ने ये भी कहा कि आप सभी के आर्शिवाद से निरतंर नौ बार विधायक बना और दिल्ली की राह भी आप लोगों के आर्शिवाद से मिला है,राज्य के विषय को दिल्ली में उठाने पीछे नहीं रहेंगे। इससे पूर्व समाज के अध्यक्ष डॉ सुरेश शुक्ला एवम कार्यकारिणी के सदस्यों ने मंत्री श्री अग्रवाल का स्वागत किया। कार्यसमिति के सदस्य संजय तिवारी ने सरयूपारीण ब्राह्मण समाज की महासभा आयोजन पर प्रकाश डाला। कोषाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने साल भर के आय व्यय का रखा।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 127 प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह रहा,सार्वाधिक शाबाशी आंजनीय दुबे व काजल पांडे ने बटोरा,काजल ने रिकार्ड बनाया है जिसका उसने मंत्री के सामने प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा सानिया मिश्रा ,नैना त्रिपाठी ,हिमांशु , अर्पिता,प्रकृति शुक्ला,अंजली दुबे ,तन्मय पांडे,श्रुति तिवारी व अन्य बच्चों का सम्मान किया गया । कार्यक्रम का संचालन राजेश त्रिपाठी ने किया ,वही मंत्री के अभिनंदन पत्र का वाचन कैलाश तिवारी ने किया।

इस अवसर पर राजेंद्र त्रिपाठी,आर एल द्विवेदी,

शैलेश शर्मा ,विनोद पांडे, अजय तिवारी,राम मूर्ति तिवारी ,विजय शंकर मिश्र ,सुरेंद्र तिवारी ,अपर्णा तिवारी ,ममता पांडे , सहित सैकड़ों विप्र जन मौजूद रहे यह जानकारी कार्य समिति के सदस्य संजय तिवारी ने दी।

कार्यक्रम में रमाकांत शुक्ला प्रेमशंकर तिवारी राममूरत तिवारी अरुण दुबे राज दुबे अनिल पाठक मुकेश पांडे,कल्याण पांडे विजय शंकर पांडे रामहृदय तिवारी संजय तिवारी हीरामणि मिश्र मथुरा तिवारी आचार्य यदुवँश मणि ,दादू भाई त्रिपाठी अजय तिवारी डॉ विजय शंकर मिश्रा बृषनेदर मिश्रा बैजनाथ मिश्र शैलेश मिश्र अजय त्रिपाठी दीपक पांडे राजेन्द्र प्रसाद पांडे,दयाशंकर पांडे विजय मिश्र विनीत तिवारी दिलीप तिवारी देवेंद्र तिवारी व्ही के मिश्र सगम त्रिपाठी, अनिल पाठक विजय मिश्र नीलकंठ त्रिपाठी सचिन पांडे राजकुमार तिवारी क्रांति तिवारी शिवशंकर तिवारी प्रमोद शर्मा सुरेंद्र तिवारी गजेंद्र तिवारी निशीकान्त त्रिपाठी उमेश मिश्र वीरेंद्र मिश्र दिनेश मिश्र उपेंद्र त्रिपाठी धनेंद्र त्रिपाठी डॉ अजय त्रिपाठी श्रीमती सीमा पांडे अपर्णा तिवारी बृजेश त्रिपाठी किरण त्रिपाठी मनोगया तिवारी राजकुमार पांडे सतीश मिश्र शिवमूरत तिवारी उमाशंकर त्रिपाठी धीरेंद्र शुक्ला विकास मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान

कहा- लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

रायपुर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के टारगेट में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनका कारोबार झारखंड का है, ये लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा, लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम शर्मा ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।

दरअसल, आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला से मिलने आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला का हाल चाल और चल रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बीजापुर के भीमापुरम गांव की घायल महिला मड़कम सुक्की के घर में नक्सलियों ने जबरदस्ती बम छिपाकर रखने कहा था। ऐसा करने से पहले गांववालों के मना करने के बाद भी नक्सली नहीं माने। जहां अचानक से आईईडी ब्लास्ट हो गया था।

प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल महिला को मुलाकात करने एम्स पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि स्पष्ट दिखता है कि नक्सली डरे हुए हैं। एम्स में मड़कम सुक्की का इलाज चल रहा है, आईडी ब्लास्ट में पैर क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि महिला का पैर नहीं बच पाएगा, किंतु जान बच जाएगी। इस घटना को लेकर एसपी से लगातार बातचीत हो रही थी। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आईईडी बम नहीं पहचानता की कौन सुरक्षा बल है, नक्सली है या ग्रामीण है। बस्तर में बारूद बिछाकर रखना बहुत गलत है। नक्सलिज्म खत्म होने की बात होनी चाहिए, माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। आचार संहिता के बाद गृहविभाग में 8 हजार पदों पर भर्ती पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल तय महीने में भर्ती की जाएगी। इसको निर्धारित किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र पर विजय शर्मा ने कहा कि जब प्रवीरचन्द्र भंजदेव की हत्या हुई थी, उस कालखंड को याद करना चाहिए। ये विष्णुदेव साय की सरकार है।

छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने आईटीएम विश्वविद्यालय को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। तीन सूत्रीय माँगो पर कार्यवाही की मांग को लेकर एनएसयूआई ग्रामीण ज़िला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने आईटीएम विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए उनके अधिकारों का हनन का मामला उठाया। मांगो को ध्यान में रखते हुए आइटीएम विश्वविद्यालय ने 8 जुलाई तक का समय माँगा है और आश्वस्त किया है कि माँगे पूरी की जायेंगी। माँग पूरी ना होने की स्थिति में रायपुर एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी । इस अवसर पर प्रदेश महासचिव निखिल वंजारी विधानसभा अध्यक्ष अंकित शर्मा ज़िला उपाध्यक्ष प्रशांत चंद्राकर ज़िला महासचिव आशीष तिवारी भूपेन्द्र साहू अमन गोस्वामी एवं समस्त छात्र/छात्राए उपस्थित थे।

छात्र छात्राओं से प्राप्त शिकायत अनुसार इनका चतुर्थ सेमेस्टर का सत्र फ़रवरी माह से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी बेहतर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए माँग की कि उनकी शिक्षा प्रणाली ऑफलाइन किया जाये। तत्पश्चात

विश्वविद्यालय छात्रो के समूह को आश्वस्त किया कि कुछ दिनों के बाद अर्थात् फ़रवरी माह के अंत तक या मार्च माह के शुरुआत तक उनकी शिक्षा प्रणाली ऑफलाइन कर दी जाएगी। चूँकि वर्तमान समय मई के अंत तक उनकी परीक्षा प्रणाली ऑफलाइन नहीं की गई है। क्योकि मई जून छात्र छात्राओ की परीक्षा प्रस्तावित है एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओ साथ वड़ा खिलाफ़ एवं उनके अधिकारों का हनन है अत: रायपुर एनएसयूआई छात्र छात्राओ के मुख्य 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के समक्ष ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में यह किया मांग

1. बी.सी.ए. [सीटीआईएस/एमएआईएस 8 के बैच 2022-25 के छात्र छात्राओं की कक्षा ऑफलाइन पद्धति से संचालित की जाये।
2. छात्र छात्राओं के निर्धारित सेमेस्टर शुल्क में महज़ 50 प्रतिशत की छूट की जाये।
3. विश्वविद्यालय द्वारा एक कमेटी गठित कर समस्त छात्र छात्राओं की माँगो को लेकर निर्णय लिया जाये और उचित निर्णय आने तक किसी भी छात्र को सेमेस्टर शुल्क अदा करने हेतु दबाव ना बनाया जाये।
4. छात्र/छात्राओ द्वारा विश्वविद्यालय को अदा की गई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की शुल्क को छात्र/छात्राओ को वापस की जाए।

कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों एवं अभिकर्ताओं की बैठक

■ **4 जून को मतगणना स्थल में अपने निर्धारित समय पर पहुंचे मतगणना अभिकर्ता : गौरव सिंह**

रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में मतगणना के परिपेक्ष्य में अभ्यर्थियो एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन समय का विशेष ध्यान रखें। मतगणना अभिकर्ताओं को सुबह 7:30 बजे तक अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जाना चाहिए। उन्हें जो टेबल निर्धारित की गई है उस पर ही बैठे।

उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों को कलेक्टोट परिसर स्थित जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम से 04 जून को सुबह 06 बजे मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार के डाक मतपत्र गणना हॉल मे ले जाया जायेगा। साथ ही अभ्यर्थी स्वयं एवं उनके अभिकर्ता चाहें तो इस समय आ कर पूरी प्रक्रिया देख सकतें हैं। मतगणना अभिकर्ता के लिए आवेदन 01

जून तक तक लिया जाएगा। रायपुर जिले के 7 विधानसभाओं के आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष 2 में और बलौदाबाजार, भाटापारा संबंधित एआरओ के पास जमा करेंगे।कलेक्टर ने कहा कि मतगणना कक्ष में मोबाईल फोन, पेन ड्राइव, साईंटिफिक कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स प्रतिबंधित रहेगे। साथ-साथ सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं आदि के उपयोग की भी अनुमति नही होगी। इसलिए इनके पाउच या पैकेट भी साथ में न रखें। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पहले मोबाइल चुराया, फिर फोन-पे के जरिए खाते से गायब कर दिए 99 हजार

रायपुर। एक शातिर चोर ने पहले मोबाइल चुराया फिर उसके फोन-पे एकाउंट से 99 हजार रुपये गायब कर दिए। युवक की शिकायत पर आजाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है।

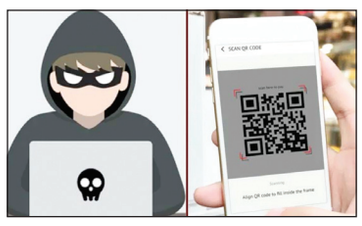

पुलिस के मुताबिक अविनाश मिश्रा 24 मई की रात करीब 8 बजे सब्जी खरीदने मंगलबाजार गया था। वहां किसी ने उनका वीवो मोबाइल चुरा लिया। मोबाइल की कीमत 15 हजार रुपए है। घर पहुंचने के बाद अविनाश ने दूसरे मोबाइल नंबर से अपने चोरी हुए मोबाइल नंबर पर कॉल किया। मोबाइल रखने वाले ने उनसे बात नहीं की, बल्कि वाट्सऐप मैसेज भेजा। वाट्सऐप मैसेज में उसने 5 हजार रुपए देने पर मोबाइल वापस करने का दावा किया। उसने कहा कि वह अगले दिन मोबाइल वापस कर देगा। इसके बाद अविनाश को शक हुआ। इसके अगले दिन वह एटीएम बूथ से मिनी स्टेटमेंट निकाला, तो हैरान रह गया। उनके बैंक खाते से अलग-अलग किस्तों में कुल 99 हजार 321 रुपए निकल गए थे। इसकी शिकायत उन्होंने आजाद चौक थाने में की। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर ने अविनाश के फोन पे का इस्तेमाल किया। इससे उसने कुछ शॉपिंग की और भुगतान उसके फोन पे के जरिए उनके बैंक खाते से कर दिया। इस तरह 99 हजार रुपए से अधिक पैसा उनके बैंक खाते से निकल गया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है।

कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों और नोडल प्राचार्य की ली क्लास

रायपुर। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निजी स्कूल संचालकों और नोडल प्राचार्यों की बैठक ली है। उन्होंने बैठक में आरटीई का पालन करना पहली प्राथमिकता की बात कही। इस अधिनियम के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे है, जिनका ऐसे स्कूलों में पढ़ना एक सपना रहता है, जो शिक्षा के अधिकार से पूरा हो रहा है। इस कार्य में उनकी अवश्य मदद करें।

उन्होंने कहा कि बच्चें अपनी शिक्षा बीच में क्यों पूरी नहीं की, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। जिला प्रशासन भी ड्रॉपआउट बच्चों के संबंध

में आवश्यक जानकारी जुटाएगा। उन्होंने कहा कि कहा कि शिक्षा पहली प्राथमिकता है। आरटीई के तहत 12वीं की पढ़ाई करने के बाद बच्चों की यह जानकारी जुटाई जाए। सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों के अच्छे शिक्षक के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उत्तम स्तर पर ले जाया जा सकता है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने कहा कि स्कूल में बेहतर समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। वे श्रेष्ठ नागरिक बनें। निजी स्कूल राईट टू एजूकेशन अधिनियम का हर संभव पालन करें। जिससे समाज के हर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने कहा कि निजी स्कूल आरटीई के रिकॉर्ड सटीक जानकारी उपलब्ध कराए। अपडेट रिकॉर्ड तैयार कर उपलब्ध कराए। जितने विद्यार्थी अध्ययनरत है, उसकी ही जानकारी दें। इस अधिनियम में 25 प्रतिशत बच्चे पढ़ाए जाने का प्रावधान है, जिसका पालन करें।

ई-वे बिल के प्रावधान में छूट समाप्त होने से बोगस और कच्ची बिलिंग पर लगेगा अंकुश

■ **ईमानदारी से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को होगा फायदा**

रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रूपए से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था, साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे

बिल कि आवश्यकता नहीं थी।

वर्ष 2018 में ई-वे बिल के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये प्रावधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टर्स को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था। देश भर में ई-वे बिल के प्रावधान लागू हुये अब 6 साल का समय हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोडकर देश के अधिकांश राज्यों में राज्य के भीतर माल के परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य है। केंद्रीय कर विभाग द्वारा भी ई-वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी गई है।

ई-वे बिल जारी करने में दिये गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बिल जारी करने वालों ने किया है, इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं परंतु सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आइ.टी.सी. का लाभ नहीं मिल पाता है। ई-वे बिल के प्रावधान लागू होने से सर्क्युलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी। ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से राज्य में कर अनुपालन के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव होगा। इससे बोगस बिल जारी करने, कच्चा बिल जारी करके कर अपवंचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।

ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर द्वारा पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच (46) को यथावत रखने किया निवेदन। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी ने बताया कि ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने पत्र के माध्यम से राज्य वाणिज्य कर मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को ज्ञापन सौंपा। चेंबर प्रतिनिधि मंडल मंत्री से समय लेकर उनसे मिलेगी तथा पूर्व में जारी अधिसूचना के अंतर्गत ईङ्क्वे बिल से संबंधित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट तथा ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगी।

चुनी हुई सरकार बंधी हो अपने वचन पत्र से

राजेश बादल

लोकसभा चुनाव-2024 की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। चंद रोज बाद नई सरकार की शक्ल भी साफ हो जाएगी। हम आशा कर सकते हैं कि अगले पखवाड़े तक वह अपना कामकाज संभाल लेगी लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस नई निर्वाचित सरकार के सामने उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं? जो भी राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार बनाए, उनके लिए या तो चुनाव पूर्व घोषित वचन पत्र/घोषणा पत्र ही काम की शुरुआत का आधार होना चाहिए। गठबंधन के हुकूमत में आने की स्थिति में साझा कार्य योजना के आधार पर सरकारी विभागों की प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति मानी जा सकती है पर, अनुभव कहता है कि व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। कुछ बरस पहले एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि सियासी पार्टियां निर्वाचन से पहले अवाम के सामने जिन वादों का पुलिंदा प्रस्तुत करती हैं, वे सत्ता में आने के बाद काफी हद तक हाशिए पर चले जाते हैं और हुकूमत के चौधरियों के अपने हित प्रधान हो जाते हैं। जनता के सामने पेश किए गए वचन पत्र को बांधकर अगले चुनाव तक के लिए अटारी पर रख दिया जाता है। जब अगला चुनाव आता है तो रंग-रोगन करके, उसकी धूल झाड़-पोंछ कर दोबारा मतदाताओं के सामने परोस दिया जाता । सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष भी निकला था कि घोषणा पत्र या वचन पत्र केवल चुनाव से पहले लोगों को लुभाने का जरिया बनकर रह गए । उनके अंदर जो बातें कही गई होती हैं, वे कभी अमल में नहीं आतीं और पार्टियों के छिपे हुए पैराशूट एजेंडे अचानक सियासी आसमान से गिरने लगते हैं। दरअसल यह हरकत लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। यह मतदाताओं को अशिक्षित मानते रहने और उन्हें सिर्फ वोट उगलने वाली मशीन समझने के कारण होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से सियासत पेशा बनी है तो राजनीतिक दल सोचने लगे हैं कि प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के वोटरों के स्वयंभू ठेकेदारों को साधना ही पर्याप्त है। चुने हुए नुमाइंदे मतदाताओं के हित में काम न भी करें तो भी क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए जीतने के बाद उनकी सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव में लगाए गए पैसे की वसूली होती है। किसी कारोबार की तरह यह पैसा भी एक तरह से पूंजी निवेश ही होता है। इसलिए निर्वाचित होने के बाद तीन बड़ी प्राथमिकताएं हर राजनेता की हो जाती हैं। एक- निवेश किए गए पैसे की वसूली, दो- उस पैसे का मुनाफा निकालना तथा तीन- अगले चुनाव के लिए लागत में बीस-पच्चीस प्रतिशत बढ़ाकर पैसा निकालकर सुरक्षित रखना। ऐसे में वचन पत्र या घोषणा पत्र का रद्दी की टोकरी में जाना स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अव्वल दर्जे पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ और विधानसभा चुनाव में पच्चीस से तीस करोड़ रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए न्यूनतम योग्यता करोड़पति होना है, न कि प्रतिभाशाली होना। भारत जैसे विकासशील मुल्क की समस्याओं को देखें तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारधारा की सरकार चुनी जाए, उसे शपथ लेते ही कम-से-कम दो साल तक सिर्फ इन तीन समस्याओं का समाधान खोजने पर ही अपने को केंद्रित करना चाहिए। मेरा मानना है कि पार्टियों को अपना वचन पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें यह उल्लेख भी होना चाहिए कि वचन पत्र के कौन से वादे पहले साल में पूरे किए जाएंगे और कौन से दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें साल में पूरे किए जाएंगे। हर साल संसद में सरकार को एक दस्तावेज पत्र पटल पर पेश करना चाहिए। इस दस्तावेज पत्र में पूरे किए गए वादों की ताजा स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए। इस पर एक कानूनी बंदिश जरूरी होनी चाहिए कि यदि कोई सरकार अगर चुनावी वादे पूरे नहीं करती तो उसे अगले चुनाव में वचन पत्र में कोई नया बिंदु जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि देश के समसामयिक घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय हालात के मद्देनजर तात्कालिक घटनाक्रम इसका अपवाद हो सकता है। अचानक युद्ध या वैदेशिक तनाव की स्थिति में सरकार अपनी नीति निर्धारित कर सकती है, पर इन तीन मसलों को हर हाल में युद्ध स्तर पर हल करना जरूरी है।

पंजाब में आपस में टकराएंगे कांग्रेस-आप

उमेश चतुर्वेदी

तपती गर्मियों के बीच अठारहवीं लोकसभा का आखिरी और सबसे दिलचस्प मुकाबला पंज प्यारों के प्रदेश पंजाब में होना है। पांच नदियों की उपजाऊ माटी के मैदान पर एक जून को दिलचस्प मुकाबला होना है। दिलचस्प इसलिए कि कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी यहां गठबंधन से अलग लड़ रही है। पूरे देश में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन पंजाब में दोनों दलों के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं।

पंजाब का मुकाबला इसलिए भी रोचक है कि यहां बरसों तक साथ रहे शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग लड़ रहे हैं। पंजाब का मुकाबला इसलिए भी ज्यादा रोचक हो गया है, कल तक कमल को खिलने से रोकने के लिए पंजा भिड़ाते रहे दिग्गज हाथ इस बार कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

देश की सबसे ज्यादा उपजाऊ पंजाब की माटी को ही माना जाता है। इस उपजाऊ जमीन पर हो रहे पंजाब के चुनावों पर असर डालने की कोशिश विदेशों में रह रहे खालिस्तानी उग्रवादी तक कर रहे हैं। खबरें यहां तक है कि भारत को तोड़ने की कोशिश में विदेशों से जुटे अलगाववादी तत्व एक खास दल को परोक्ष सहयोग दे रहे हैं। खुफिया ब्यूरो रह-रहकर इस सिलसिले में चेताता भी रहता है।

यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि एक बरस से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन में पर्दे के पीछे से भी अलगाववादी ताकतें साथ दे रही थीं। पंजाब की धरती इन दिनों नशे के कारोबारियों की भी चपेट में है। वे राजनीति को भी नशे का डोज देने की कोशिश में हैं। पंजाब के चुनाव नतीजों पर इन सबका असर पड़े बिना नहीं रहेगा।

सोशल मीडिया पर अपनी तीव्र और आक्रामक पहुंच के जरिए आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का दावा अक्सर करती है। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी महज 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा 13 सीटें पंजाब की ही हैं। दिल्ली की सात, हरियाणा की एक और गुजरात में एक सीट पर ही आप लड़ रही है। अब तक पंजाब

में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है।

2019 के आम चुनावों में आप पार्टी को सिर्फ 7.38 प्रतिशत ही वोट मिले थे और उसे सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 40.12 प्रतिशत वोट और आठ सीटें मिली थीं। कांग्रेस की पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी शिरोमणि अकाली दल को 27.76 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिलीं थी, जबकि उसकी सहयोगी रही बीजेपी को 9.63 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिली थीं।

पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा था। क्योंकि उसके पहले यानी 2014 के आम चुनावों में पार्टी को 24.4 प्रतिशत वोट और चार लोकसभा सीटें मिली थीं। तब शिरोमणि अकाली दल को 26.30 प्रतिशत वोट और चार सीटें मिली थीं। तब उसकी सहयोगी रही बीजेपी को 8.70 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिली थीं। सबसे ज्यादा यानी 33.10 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस के महज तीन लोकसभा सांसद ही चुने जा सके थे।

लेकिन इसी आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी। तब उसे 42.10 प्रतिशत वोट मिले और 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 विधायक जिताकर देश को चौंका दिया था। पार्टी ने इसी वजह से मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी उम्मीद लगा रखी है। यही वजह है कि उसने कांग्रेस के साथ यहां चुनावी समझौता नहीं किया। अगर समझौता करती तो उसे साझा तरीके से लड़ना पड़ता।

वैसे कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व भी ऐसी ही सोच के साथ पंजाब में आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस ने अपने राज्य नेतृत्व के दबाव में साझा लड़ने के बजाय अकेले उतरने की तैयारी की। दोनों दलों के लिए अच्छी बात यह है कि पारंपरिक सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी अलग-अलग मैदान में हैं। दोनों दलों के बेहतर रिश्तों के दौर में बीजेपी हमेशा शिरोमणि अकाली दल के छोटे भाई की भूमिका में रही है। बीजेपी की इस भूमिका से नवजोत सिंह सिद्धू नाखुश रहते थे। वे बीजेपी को अग्रिम पंक्ति में लाना चाहते थे। इसी वजह से वे शिरोमणि अकाली दल के निशाने पर रहे।

यहां यह याद करना जरूरी है कि राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि उन्होंने ही दी थी। यह बात और है कि अब वे कांग्रेस के साथ हैं। अब सिद्धू बीजेपी से बाहर हैं, लेकिन बीजेपी छोटे भाई की भूमिका से आगे निकलकर राज्य में अपना स्थान बनाने की कोशिश में है। गठबंधन के दिनों में चूंकि पार्टी सीमित सीटों पर ही ध्यान केंद्रित करती रही, लिहाजा वह राज्य में नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई। जब पार्टी ने खुद के दम पर मैदान में उतरने की सोची तो उसके पास उम्मीदवारों का अकाल नजर आया।

लिहाजा उसने कांग्रेस के स्थापित नेतृत्व रहे लोगों की ओर निगाह डाली। अपनी पार्टी में वे लोग भी नाखुश थे तो बीजेपी ने उन्हें साथ जोड़ लिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब की पटियाला से सांसद रहीं परणीत कौर, पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता रवनीत सिंह बिट्टू आदि को बीजेपी ने शामिल कर लिया और मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिन्दर के मैदान में न होने की कमी कांग्रेस को ही नहीं पूरे पंजाब को जरूर खल रही होगी। जो नेता महज दो साल पहले तक राज्य में कमल को खिलने से रोकते रहे, वे ही अब राज्य में कमल खिलाने की कोशिश में प्राणपण से जुटे हुए हैं।

पंजाब में बीजेपी की संभावना कम दिख रही है। किसान आंदोलन के चलते वह सबसे ज्यादा किसानों के निशाने पर भी रही है। राज्य में उसकी छवि शहरी पार्टी की ही रही है। लेकिन सभी शहरों में उसकी उपस्थिति नहीं रही। अब उसे राज्य की शहरी आबादी के साथ ही यहां की करीब 38 फीसद हिंदू आबादी से उम्मीद है। अगर विपरीत परिस्थिति में भी वह अपना खाता खोल पाती है या राज्य की तेरह में से दो-तीन सीटें झटक लेती है तो भविष्य के लिए उसकी राह आसान हो जाएगी।

वहीं कांग्रेस की कोशिश अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखने की है। हालांकि इस बार ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि उसका तकरीबन नब्बे फीसद शीर्ष नेतृत्व उसका साथ छोड़ गया है। शिरोमणि अकाली दल को लेकर जनता का उत्साह खास नजर नहीं आ रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की तो स्वाति मालीवाल की पिटाई प्रकरण के बाद वह भी बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि वह विधानसभा चुनाव जैसे नतीजे की उम्मीद में है। लेकिन राज्य से आ रही खबरें पार्टी के लिए इतनी सुकूनदायक नहीं हैं।

वैसे आखिरी फैसला मतदाता को ही करना होता है। एक जून को ईवीएम का बटन दबाकर वह अपना फैसला सुनाएगा। देखना यह है कि वह झाड़ू फिराता है या पंजे को मजबूत करता है या फिर कमल खिलाता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामणि उपनिषद् (भाग-14)

गतांक से आगे...

यह प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगुनी अर्थात् छत्तीस मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात् सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम में शरीर काँपने लगता है तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए।

योग का अभ्यास करने के लिए एकान्त में बद्धपद्मासन लगाकर बैठे और शिवस्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन नव द्वारों से वायु का गमनागमन होता है, उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अग्नि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा कुण्डलिनी मार्ग से दृढ़तापूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करे। जब तक यह स्थिर रहे, तब तक वह (अन्य) महापुरुष की संगति नहीं चाहता अर्थात् वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है।

संसार-सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है। योग के आसनों से (शारीरिक) रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानसरोग (विकार) समाप्त होते हैं।

योग की धारणाशक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान् बनता है, समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है। बारह बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा बारह बार इसी तरह प्रत्याहार करने से शुभफलदात्री धारणा की सिद्धि होती है।

क्रमशः ...

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस

नई दिल्ली। हर साल 29 मई को विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए यह दिन स्थापित किया गया था। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। आज के दिन दुनियाभर में उन सभी महिलाओं और पुरुषों के कार्य की सराहना तथा सम्मान के लिए भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) द्वारा इस अवसर पर छह डाक टिकटों का संग्रह जारी किया गया।

साल 1948 से यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत 3,900 से अधिक शांति सैनिकों को संपूर्ण विश्व में

शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गंवाई।

शांति सेना का गठन 29 मई 1948 को किया गया था। इस सेना का पहला मिशन इजरायल-अरब शांति के लिए था। अब तक दुनिया के 72 अलग-अलग मिशन में शांति सेना की तैनाती हो चुकी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के दुनियाभर में 14 शांति अभियान चल रहे हैं। यह सेना जिन 14 अभयिान में शामिल हैं, उनमें अफ्रीका और एशिया के कई देश शामिल हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, दक्षिणी सूडान, साइप्रस, तिमूर, कांगो, सियरा लियोन, लेबनान, पश्चिमी सहारा, माली, अबेयी, हैती और मध्य-पूर्व के देश हैं।

वर्तमान में शांति सेना में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के 87 हजार जवान हैं। इनमें सैनिक, पुलिस और आम नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण एशियाई देशों के जवान हैं। इनमें बांग्लादेश के 6,709, नेपाल के 5,706 और भारत 5,581 जवान हैं। इसके बाद पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका हैं।

शांति सेना का जितना भी खर्च आता है उसे वहन करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की होती है। शांति सेना के लिए हर साल कितना बजट जारी होगा, यह तय करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद लेती है।

संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं है और शांति सेना के सदस्य अपने देश की सेना के सदस्य ही रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग की कैप लगाते हैं या नीले रंग के हेल्मेट पहनते हैं, जो अब इस सेना की पहचान बन गई है। अपने देश में भी संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक तैनात रह चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर पर किये गए हमले की शिकायत लेकर 6 जनवरी 1948 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की धारा 35 के नियमों के तहत सुरक्षा परिषद में गया था, इसलिये भारत पर हुए पाकिस्तान के हमले के विषय पर 6 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने कभी अमल ही नहीं किया।

खुद के अस्तित्व के लिए कट्टर बने रहना इस्राइल की मजबूरी

निर्मल कांत

इस्राइल को कोसने वाले यह समझें कि वह बदल नहीं सकता, क्योंकि यह लड़ाई उसके अस्तित्व की है। लेकिन अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा और खुद को इस्लामी क्रांति का अगुआ मानने वाला ईरान भूल रहा है कि लंबे समय में क्रांतियां उन्हीं मूल्यों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जिनके लिए वे लड़ी गई थीं।

मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट दो तारीखों से संबंधित एक सवाल पर आधारित है कि 1948 और 1979 में से किस ऐतिहासिक क्षण के पलटने की संभावना है? ये तारीखें इस्राइल के निर्माण और उसके 31 साल बाद ईरानी क्रांति से संबंधित हैं। इस प्रश्न का निहितार्थ यह है कि यहूदी राज्य और इस्लामी गणतंत्र स्थायी रूप से एकसाथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, कम से कम तब तक, जब तक दूसरा (इस्लामी गणतंत्र) पहले (यहूदी राज्य) को खत्म करने की चाह रखता हो। हाल के दिनों ने उनके पतन के दो संभावित माध्यमों को चर्चा में ला दिया है।

सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इस्राइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन करेंगे। यह अलग बात है कि इस फैसले से दोषसिद्धि तो दूर की बात है, किसी की गिरफ्तारी भी संभव नहीं है। बाइडन प्रशासन ने पहले ही इस फैसले की निंदा की है और यहां तक कि जिन देशों के इस्राइल से कम दोस्ताना रिश्ते हैं, वे भी मानते हैं कि परमाणु हथियार संपन्न और ताकतवर खुफिया एजेंसी वाले किसी राष्ट्र के नेता की गिरफ्तारी संभव नहीं है। लेकिन यह घोषणा उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत इस्राइल के विरोधी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता खत्म करने और

अलग-थलग करने से धीरे-धीरे इस्राइल पतन की ओर अग्रसर होगा।

यहां तक कि नेतन्याहू और गैलेंट के साथ हमास के तीन नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करने का करीम खान का फैसला भी उसी समग्र रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यह इस्राइली नेताओं को नैतिक स्तर पर आतंकवादियों के साथ रखता है। फिर हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और छह अन्य लोगों की मृत्यु भले ही दुर्घटनावश हुई हो। लेकिन इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस हेलिकॉप्टर में वे थे, उसे घरेलू या विदेशी साजिशकर्ता द्वारा गिराया गया। दुर्घटना का जो भी कारण हो, यह शासन के लिए विश्वासघात और पूर्वाभास को समझने में कमजोरी दोनों को दर्शाता है। विश्वासघात इसलिए कि सक्षम राष्ट्रों को अपने अति विशिष्ट व्यक्तियों को बिना दुर्घटना के विमान में ले जाने में सक्षम होना चाहिए। और %पूर्वाभास में कमी% इसलिए कि 1980 के दशक में हजारों कैदियों को फांसी पर चढ़ाकर अपना दबदबा कायम करने वाले रईसी को व्यापक रूप से ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। ऐसे में, उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी।

अब ईरान को 50 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे, जो शासन की गंभीर अलोकप्रियता को उजागर करेगा। वर्षों से मतदान का प्रतिशत घटता जा रहा है, क्योंकि खामेनेई चुनावी मैदान में सबसे कट्टर उम्मीदवारों को ही उतारते हैं। यह उनके उत्तराधिकार के लिए सत्ता संघर्ष का मंच भी तैयार करता है, खासकर खामेनेई के अलोकप्रिय बेटे मोज्तबा को उत्तराधिकार सौंपने के प्रति व्यापक अनिच्छा को देखते हुए शासन को उनकी इच्छा से प्रभावी ढंग से राजशाही में बदल दिया गया है।

अगर गंभीर आर्थिक संकट को 2022 के विरोध प्रदर्शन के क्रूर दमन से उपजे गुस्से के साथ जोड़ दें, तो गंभीर अस्थिरता की आशंका या शासन के अचानक पतन का खतरा वास्तविक महसूस होने लगता है। ऐसे में, यही सवाल उठता है कि इस्राइल या ईरान में से किस पर संकट ज्यादा है? जैसा कि पूर्व ईरानी राष्ट्रपति अकबर रफसंजानी ने एक बार कहा था। इस्राइल के लिए सबसे गंभीर खतरा यह है कि %एक परमाणु बम समूचे इस्राइल को खत्म कर देगा। लेकिन इससे इस्लामी जगत को सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए, इस पर विचार करना अतार्किक है। ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमताओं (और उस बारे में अस्पष्टताओं) को लेकर पश्चिमी दुनिया को जरूर चिंतित होना चाहिए। लेकिन आईसीसी के कदमों से या फिर शैक्षिक संस्थानों में विरोध जताने से इस्राइल को न के बराबर खतरा है। उनकी सोच यह है कि इस्राइली लोगों को एक खास क्षेत्र में बसाया नहीं गया था। यहूदियों का मानना है कि वे मूल रूप से इस्राइल से हैं।

यहूदीवाद इतिहास का सबसे पुराना उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष है, जो रोमन युग में शुरू हुआ था। जहां तक इस्राइली यहूदियों के अपने पूर्वजों की भूमि पर लौट जाने की बात है, तो सवाल उठता है कि उनके पूर्वजों की भूमि कहां है और क्या है। रूसी नरसंहार या अरब नरसंहार या सामूहिक नरसंहार की भूमि ? इस्राइल के कटु आलोचक इसे भूल जाते हैं, लेकिन इस्राइली नहीं। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, यह तथ्य अब यहूदी प्रवासी समुदायों के प्रति नफरतों से उजागर है। इस्राइल पर अपने दुश्मनों के समक्ष नरम पड़ने के लिए जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही यहूदीवाद पैदा होगा। यह कट्टरता यहूदी पहचान से जुड़ी हुई है। ईरान में शासन के लिए मुख्य खतरा भीतर से और नीचे से आता है। वहां की स्थितियों में यह भूलना आसान है कि 2022 में हिजाब और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि शासन बेहद हिंसक तरीकों के असंतुष्टि को दबाने में सफल रहा है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों की बढ़ती आवृत्ति से स्पष्ट है कि शासन के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

रईसी की मौत के साथ शासन को जो समर्थन मिल भी रहा है, वह बंट सकता है। अर्थशास्त्र का एक अनौपचारिक नियम, जिसका नाम हर्बर्ट स्टेन के नाम पर रखा गया है, के अनुसार, जो प्रवृत्तियां जारी नहीं रह सकतीं, वे नहीं रहेंगी। यह नियम राजनीतिक अस्तित्व पर भी लागू हो सकता है। ईरान की तरह इस्राइल में भी घरेलू कमजोरियां हैं, जिनमें से कुछ ही सात अक्तूबर से पहले न्यायिक सुधार को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के रूप में सामने आई थीं। लेकिन ईरान के शासकों के लिए जोखिम अधिक गंभीर हैं। उन्होंने हमेशा इस्लामी क्रांति का अगुआ होने का दावा किया है, लेकिन लगता है कि वे यह भूल गए हैं कि क्रांतियों द्वारा उन्हीं मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का इतिहास रहा है, जिनके लिए वे लड़ी गई। बड़े पैमाने पर ईरान के लोग इस्लामवादी नहीं रहना चाहते। लेकिन खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए कट्टर बने रहना इस्राइल की मजबूरी है और वह इसके लिए लड़ेगा।

आज का इतिहास

1780 अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध-ए के मुख्य रूप से वफादार बल ने महाद्वीपीय सेना के सैनिकों के आत्मसमर्पण को अस्वीकार कर दिया और पैट्रियोट्सोल्डियर्स को मारना जारी रखा, जिसमें वे पुरुष भी शामिल थे जो विरोध नहीं कर रहे थे।
1790 रोड आइलैंड ने संयुक्त राज्य के संविधान की पुष्टि की और ऐसा करने वाला 13 मूल राज्यों में से अंतिम राज्य बन गया।
1852 स्वीडिश ऑपेरेटिव सोप्रानो जेनी लिंड ने शोमैन पी। टी। बार्नम के प्रबंधन के तहत अमेरिका के एक सफल कॉन्सर्ट दौरे का समापन किया।
1861 हांगकांग जनरल चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गयी।
1867 ऑस्ट्रो-हंगेरियन समझौता द्वारा, फ्रांज जोसेफ आईओएफ ऑस्ट्रिया द्वारा हस्ताक्षरित और फेरेंस डेक के नेतृत्व में एक हंगरी प्रतिनिधिमंडल, ऑस्ट्रिया-हंगरी के दोहरेमोनार्की की स्थापना की गई थी।
1874 स्विट्ज़रलैंड में वर्तमान संविधान प्रभावी किया गया।
1911 अंग्रेजी नाटककार डब्ल्यू। एस। गिलबर्ट की गीतकार जोड़ी गिल्बर्टैंड सुलिवन की मौत हो गई, जबकि एक युवती को उसकी झील में डूबने से बचाया गया।
1913 इगोर स्ट्राविंस्की के बैले द रीट ऑफ स्प्रिंग ऑफ दी थिएट्रे डेस चैंप्स-एलिसीस इन पेरिस के प्रीमियर के दौरान, संगीत और कोरियोग्राफी के अवंत-विभाव प्रकृति ने दर्शकों में एक निकट-दंगा का कारण बना।
1914 आयरलैंड के महासागर लाइनर आरएमएस महारानी सेंट लॉरेंस नदी में स्टॉरस्टाड से टकराकर डूब गए, जिसमें 1,012 जहाज पर सवार हुए।
1915 तोफिलोब्रागा पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने।
1935 सबसे अधिक उत्पादित लड़ाकू विमान इन्हिस्टोर के मेसर्शचिट बीएफ 109 की पहली उड़ान थी।
1942 बिंग क्रॉस्बी ने व्हाइट क्रिसमस गीत के अपने संस्करण को रिकॉर्ड किया, जो कि अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एकल बन गया, जिसकी 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं।
1947 फ्लुगेलैग द्वीपसमूह पर एक हवाई जहाज पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 25 लोग मारे गए।
1953 एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।
1959 चार्ल्स दि गाल फ्रांस के राष्ट्रपति बने।

केवल शेषन ही क्यों, गिल और चावला पर भी चर्चा हो

अजय सेतिया

विपक्ष ने 2014 के बाद नियुक्त हर मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। मोदी सरकार बनने के बाद अचानक ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाने लगे। कुछ एनजीओ ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीमकोर्ट चले गए। ईवीएम का विकास इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुआ था और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया वही चल रही थी जो जवाहर लाल नेहरू ने शुरू की की थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी उसी प्रक्रिया को अपनाया था और बाद में नरेंद्र मोदी भी वही प्रक्रिया अपना रहे थे। विधि मंत्रालय सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर्ड अधिकारियों की सूची बनाता था, फिर उसमें से तीन का चयन होता है, जिसे प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता था। प्रधानमंत्री सलाह मशविरा करके राष्ट्रपति को नियुक्ति की सिफारिश भेज देते थे।

हालांकि संविधान सभा ने उम्मीद की थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का एक ढांचा विकसित किया जाएगा, लेकिन नेहरू से लेकर मोदी तक किसी ने कोई ढांचा विकसित नहीं किया था। जो मनमानी प्रक्रिया नेहरू ने अपनाई थी, उसे सभी अपनाते रहे। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक लॉबी को तरह तरह की आशंकाएं सताने लगी और वे 2015 में ही सुप्रीमकोर्ट पहुंच गए। ढेरों याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन्हें सुप्रीमकोर्ट ने 2018 में पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंप दिया।

जस्टिस के. एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 2 मार्च 2023 को फैसला सुनाया कि जब तक संसद से क़ानून नहीं बनता, तब तक चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस का पैनल करेगा। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अलग से प्रक्रिया ही नहीं है, वह वरीयता के आधार पर बनता है। स्वाभाविक है चीफ जस्टिस का पैनल में शामिल किया जाना सरकार को नागवार गुजरा। सरकार ने अगस्त में ही नियुक्ति प्रक्रिया का नया बिल बना कर संसद में पेश कर दिया, जिसे दिसंबर 2023 में संसद ने पास भी कर दिया। इस बिल में चीफ जस्टिस की जगह केंद्र सरकार का एक मंत्री कर दिया गया था। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था, लेकिन जब संसद ने पास कर दिया तो कांग्रेस ने क़ानून को सुप्रीमकोर्ट में फिर चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक पीठ के आदेश का उल्लंघन है। कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस बीच एक चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पांडे रिटायर हो गए और लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले 9 मार्च को एक अन्य आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया।

कांग्रेस चाहती थी कि जब तक सुप्रीमकोर्ट उनकी याचिका पर फैसला न करे, तब तक कोई चुनाव आयुक्त नियुक्त न किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने पैनल के कांग्रेसी सदस्य अधीर रंजन चौधरी के विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर दो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। ये नियुक्तियां चुनावों की घोषणा से 48 घंटे पहले हुई थी। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में दो टूक शब्दों में कहा कि क्या किसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता तभी सिद्ध होगी, जब सिलेक्शन पैनल में ज्यूडिशियल मेंबर हो। सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण नई नियुक्तियों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। जिस दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दिन से कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों जब राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचारकों के खिलाफ आई शिकायतों पर चुनाव आयोग ने उस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की, तो इस पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के खिलाफ आई शिकायत पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को और राहुल गांधी के खिलाफ आई शिकायत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे को नोटिस दिया था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि उसने प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई है।

चुनाव आयोग और आयोग के सदस्यों की आलोचना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन 23 मई को एक इंटरव्यू में उन्होंने गढ़े मुर्दे उखाड़ दिए, जब उन्होंने बिना नाम लिए टी.एन. शेषन की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 1999 में गुजरात की गांधीनगर सीट पर भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवानी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब टी.एन. शेषन एक मात्र चुनाव आयुक्त थे। परंपरा यह है कि चुनावों के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मौत हो जाती है, और तब तक उसकी सीट पर वोटिंग नहीं हुई हो, तो सिर्फ उस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है और बाद में नई नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनाव करवाया जाता है। लेकिन राजीव गांधी के करीबी रहे शेषन ने 21 दिन तक बाकी सभी सीटों पर चुनावों को स्थगित कर दिया था। हालांकि देश के सात मुख्यमंत्रियों ने 21 दिन तक चुनाव स्थगित करने का विरोध किया था, लेकिन शेषन ने किसी की नहीं सुनी थी।

कांग्रेस ने इन 21 दिनों में राजीव गांधी की अस्थियों को देश भर में घुमा कर कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाया। कांग्रेस के विज्ञापनों में राजीव गांधी की अंतिम यात्रा के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया जिस कारण कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति पैदा हुई और चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस सरकार बन गई। टी.एन. शेषन की नियुक्ति चन्द्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गाधी की सलाह से ही की गई थी। क्योंकि उस समय चंद्र शेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन पर ही टिकी हुई थी।

नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में इसी घटना की याद दिला कर बताया कि कांग्रेस किस तरह के चुनाव आयुक्त नियुक्त करती थी, यह उनका ट्रेक रिकार्ड है। हालांकि मोदी ने चुनाव आयुक्त का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस समय की घटना का उन्होंने जिक्र किया, उस समय टी. एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टी.एन. शेषन के बारे में छवि है कि उनसे निष्पक्ष और दबंग मुख्य चुनाव आयुक्त कोई हुआ ही नहीं। हालांकि यह भी तथ्य है कि उन्हीं के समय बिहार में जमकर बूथ केप्चरिंग हुआ करती थी और वह लालू यादव एंड कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। शेषन के तानाशाहीपूर्ण व्यवहार से प्रधानमंत्री नरसिंह राव बहुत क्षुब्ध थे, इसलिए उन पर नकेल डालने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को एक सदस्यीय से तीन सदस्यीय बना दिया था।

टी.एन. शेषन के रिटायरमेंट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बने एम.एस. गिल भी कांग्रेस के करीब थे। एम.एस. गिल को तो उनके कार्यकाल के तुरंत बाद सोनिया गांधी ने पंजाब से कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य बना दिया था। उन्हें दो टर्म तक राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और मनमोहन सरकार में मंत्री भी बनाया गया। बाद में यूपीए सरकार के समय 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने नवीन चावला तो सोनिया गांधी के व्यक्तिगत वफादार थे। उनके कांग्रेस के साथ पुराने संबंधों के चलते जब 2006 में उनकी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई थी, तो बहुत हंगामा हुआ था। उनकी नियुक्ति को उस समय के राज्यसभा के विपक्ष के नेता जसवंत सिंह ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए 200 सांसदों ने उनके खिलाफ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को याचिका देकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी।

बाद में भी उनका व्यवहार एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जैसा ही था, जब चुनाव आयोग ने एक मामले में सोनिया गांधी को नोटिस देने का फैसला किया था, तो चावला ने उसका विरोध किया। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने तो उन्हें हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भी की थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने राष्ट्रपति को भेजी गई उन्हें हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव नवीन चावला ने ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में करवाए।

आधी आबादी के साथ राजनीतिक छल

राजकुमार सिंह

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देनेवाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी आधी आबादी के प्रति राजनीतिक दलों के व्यवहार में बदलाव नहीं दिखता। महिला सशक्तिकरण की बात सभी दल करते हैं, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने का मौका आता है तो कन्नी काट लेते हैं। आधी आबादी के हिस्से बमुश्किल 10-15 प्रतिशत टिकट ही आती है, उनमें भी ज्यादातर पर कब्जा राजनीतिक परिवारों से आनेवाली महिलाओं और सेलिब्रिटी मानी जानेवाली महिलाओं का रहता है। आम परिवारों से आनेवाली राजनीतिक कार्यकर्ता अक्सर ठगी-सी महसूस करती हैं। पिछले साल भारी सस्पेंस के बीच नए संसद भवन में हुए विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करते वक्त लंबे-चौड़े वायदे किए गए थे, लेकिन उनकी कलई इन लोकसभा चुनावों में खुल गई है। वायदा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का था, लेकिन इन चुनावों में पांचवें चरण तक उन्हें टिकट देने का प्रतिशत 12 पर ही पहुंच पाया है। बेशक संसद द्वारा पारित विधेयक में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की तारीख तय नहीं, लेकिन उसके बाद हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में उस दिशा में ईमानदार पहल तो दिखनी चाहिए थी। वह विधेयक पारित होने के बाद पिछले साल के अंत में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से भी राजनीतिक दलों की कथनी-करनी में भारी अंतर दिखा था। फिर भी उम्मीद थी कि जिस संसद ने महिला आरक्षण पर मुहर लगाई, उसके चुनाव में तो टिकट वितरण में कुछ गंभीरता दिखेगी। आलम यह है कि पहले दो चरणों के मतदान में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत मात्र आठ रहा। तीसरे चरण में यह प्रतिशत नौ तक पहुंचा और चौथे चरण में दस तक। पांचवें चरण में यह 12 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। क्या यह देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी से छल नहीं है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में बहस के दौरान और उसके बाद बाहर भी, राजनीतिक दलों के वायदों का क्या हुआ? टिकट देने में यह उदासीनता क्या इसलिए है कि अभी तक संगठन में भी महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में नहीं लाया जा सका है? जो राजनीतिक दल संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को एक-तिहाई हिस्सेदारी नहीं दे सकते, वे संसद और विधानसभाओं में वास्तव में दे देंगे, यह दिवास्वप्न ज्यादा लगता है। यह भी शेष राजनीतिक दलों पर बेहद तल्ख टिप्पणी है कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल देश में एकमात्र ऐसा दल है, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देने की अपनी वचनबद्धता पर हर चुनाव में ईमानदारी से अमल भी करता है।

बिना किसी नारे के बीत जाएगा चुनाव ?

बिक्रम उपाध्याय

आरोपों-प्रत्यारोपों और व्यक्तिगत आक्षेपों से भरे इस चुनाव में एक कमी जो दिखाई दी है वह है अच्छे नारों और मुहावरों की। नए और प्रभावशाली वाक्यांश हमारे लोकतंत्र के गहने रहे हैं। लेकिन इस बार अच्छे नारों और स्लोगनों के बिना जैसे चुनाव अधूरा लग रहा है।

चुनावी नारे या काव्यांश राजनीतिक माहौल को हमेशा सरस और चुटीले बनाते रहे हैं। जनता की कल्पना को मूर्त रूप देने में भी ये नारे बड़े प्रभावशाली होते हैं। जैसे कभी %जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर% लोगों ने विश्वास किया था उसी तरह %अबकी बारी, अटल बिहारी% पर भी लोगों ने यकीन जताया था। 2014 में खुद भाजपा ने अबकी बार, मोदी सरकार पर वोट की फसल काटी थी। चुनावी नारे पूरे देश में गूंजते रहे हैं और चुनावी अभियानों को मजबूती देते रहे हैं। नारे लोकतंत्र की जान हैं। वे माहौल बनाते हैं, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संबंध बनाते हैं और चुनावी रैलियों में जोश भरते हैं। उनके बिना चुनाव अधूरा लगता है। कभी नारों से दीवारें पटी होती थीं पर अब नये चुनावी नियमों के कारण यह चलन खत्म सा हो गया है। चुनाव में नारे लोगों को इसलिए भाते हैं, क्योंकि हम भारतीय हमेशा से अपनी भावनाओं को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का उपयोग करते रहे हैं। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी नारों और हुंकारों के जरिए परिवर्तन की बात करते रहे हैं।

अभी से नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के समय से ही काव्यांश और नारे ज्यादा असरदार साबित हुए। कुछ नारे तो इतने चर्चित और लोकप्रिय हुए कि उन्हीं से नेताओं की अलग पहचान बन गई। जैसे जय हिंद के घोष से आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि जुड़ी हुई है। उसी तरह

से वंदे मातरम् गान के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय का नाम साइमन गो बैक के नारे के साथ अमर हो गया, तो अंग्रेजों भारत छोड़ों के नारे के कारण बापू सहज याद आ जाते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया।

इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि भारतीय जनमानस पर नारों पर कितना असर होता है। इसलिए आजाद भारत में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से नारों का उपयोग भी शुरू हो गया। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ। अपने पहले चुनाव में प्रधानमंत्री नेहरू ने सांप्रदायिकता के खिलाफ कई नारे उछाले। जैसे -किसी एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को दबाने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। बाद में 1962 के चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के कारण नेहरू के खिलाफ यह नारा काफी लोकप्रिय हुआ कि वाह रे नेहरू तेरी मौज, घर में हमला बाहर फौज। इस नारे के जरिए विपक्ष ने नेहरू द्वारा भारतीय सेना के कुछ जवानों को देश के बाहर भेजने के फैसले पर सवाल उठाया था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और उनका दिया हुआ नारा %जय जवान जय किसान% आज भी बड़े शान से लिया जाता है। हालांकि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेई ने जब पोखरन परमाणु विस्फोट किया तो इस जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी जोड़ कर इसे अमर बना दिया। चुनावों के दृष्टिकोण से देखें तो अब तक सबसे असरदार नारा इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा रहा है, जो उन्होंने 1971 के चुनाव के समय दिया था। हालांकि 1971 के चुनाव के बाद से ही इंदिरा गांधी के दुर्दिन भी शुरू हो गए, और उसकी पराकाष्ठा 1975 में आपातकाल के रूप में हुई। बाद में जब पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया तब जयप्रकाश का यह नारा बुलंदियों पर पहुंचा कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी 1980 में चुनाव में गयीं तो उन्होंने नारा दिया सरकार वह चुनें जो चल सके। जाहिर है आपातकाल के बाद जनता पार्टी का सरकार बनाने का प्रयोग विफल रहा और ढाई साल में ही दो प्रधानमंत्रियों के आने के बाद भी सरकर पांच साल चल नहीं सकी। 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की शहादत पर लड़ा गया था। परंतु जब 1991 के चुनाव प्रचार में राजीव गांधी उतरे तो उन्होंने नारा दिया-% वोट स्थिरता के लिए, वोट कांग्रेस के लिए%। 1996 के आते आते भाजपा की राजनीतिक पकड़ देश पर होने लगी, तो भाजपा ने नारा दिया - सबको परखा बारी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी। उसके तुरंत बाद भाजपा ने एक और चुनावी नारा दिया- राम, रोटी और स्थिरता और इसका असर भी हुआ। भाजपा लगभग केंद्र में 6 साल सरकार चलाने में सफल रही। लेकिन 2002 में जब भाजपा ने अपना चुनाव स्लोगन इंडिया शाइनिंग दिया तो लोगों ने इसे नहीं अपनाया और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। केवल देश के आम चुनाव में ही नारे या स्लोगन हिट नहीं हुए, बल्कि राज्यों के चुनाव में भी नारों का बड़ा असर रहा। बंगाल में ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया और सत्ता में आ बैठी।

मतदान से उदासीन क्यों हो रहे हैं मतदाता?

उमेश चतुर्वेदी

भारत जैसे देश में जहां करीब साठ फीसदी आबादी युवा यानी पैंतीस साल से कम आयु वर्ग की है, जहां की साक्षरता दर अस्सी प्रतिशत के करीब है, जहां राजनीतिक जागरूकता का स्तर भी बेहतर स्थिति में है, वहां मतदान के कम होने के तात्कालिक कारण हो सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर जनता की मतदान के प्रति बढती उदासीनता जिम्मेवार है। भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, राजनीतिक दल उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। हम अक्सर राजनीतिक दलों की साख का आकलन उनके नेतृत्व की साख की बुनियाद पर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण अंग उनके कार्यकर्ता की अहमियत को भुला देते हैं।

जिस लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है, उसमें राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा का मूल आधार उसकी कामयाबी है, उसके कार्यक्रमों और सिद्धांतों का नंबर उसके बाद आता है। और राजनीतिक दल की कामयाबी नेतृत्व की साख और उसके कार्यक्रमों के साथ ही उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता की वजह से हासिल होती है। राजनीतिक तंत्र का कार्यकर्ता वह औजार है, जो नेतृत्व की साख और उसके कार्यक्रमों को आम मतदाताओं तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में नेतृत्व द्वारा दिखाए सपनों को वह मतदाताओं के मन में छलांग लगाने को प्रेरित करता है। स्थानीय स्तर पर चूंकि वह लगातार आम मतदाताओं के सीधे संपर्क में रहता है, उसके सुख-दुख में शामिल रहता है, इसलिए उसकी बात मतदाता कुछ ज्यादा ही गौर से सुनता है। मतदान के दिन अगर मतदाता वोटिंग के प्रति उदासीन हो रहा होता है, तब यह कार्यकर्ता ही अपने रोजाना के संबंधों के दम पर मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाता है।

कार्यकर्ता भी दो तरह के होते हैं। कुछ राजनीतिक दल विचारधारा आधारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इनके कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हें कैडर कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर पर आज चमक रही है तो उसमें उसके कार्यक्रमों और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल के साथ ही उसके कैडर का भी महत्वपूर्ण योगदान

है। याद कीजिए पिछले दो आम चुनावों को। मनमोहन सरकार पर लगे चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोपों, मंत्रियों और सांसदों की जेल यात्राओं, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला आदि के साथ ही निर्भया कांड से देश में क्षोभ का माहौल था।

इस माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने में उसके कैडर का गहन योगदान रहा। जब उसके सामने चुनाव आए तो उसने बदलाव के लिए पूरे उत्साह से काम किया। इसका नतीजा यह रहा कि 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। निश्चित तौर पर मोदी के करिश्माई और साखदार नेतृत्व ने लोगों को बीजेपी की ओर आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस बार पार्टी के उसी कैडर में उत्साह कम नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर विगत के दो आम चुनावों की तरह उसका उत्साह नजर नहीं आ रहा है।

सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तमाम दलों के कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा। जिसका नतीजा कम मतदान के रूप में दिख रहा है। बेशक तीखी गर्मी की लहर के चलते मतदाता घरों से वोटिंग के लिए बाहर निकलने से हिचक रहा है। अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह होता तो वह मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए मेहनत करता। वह उन्हें उत्साहित करता। चुनावी पंडितों को लगता है कि कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग होता जा रहा है। कैडर आधारित पार्टियों के कार्यकर्ताओं में यह प्रवृत्ति कुछ ज्यादा नजर आ रही है।

महाराष्ट्र में मतदान में कुछ ज्यादा ही कमी दिख रही है। यह संयोग है या कुछ और कि वहां शिवसेना के दोनों धड़े और बीजेपी कैडर आधारित पार्टियां हैं। मतदान की कमी ज्यादातर उन सीटों पर दिख रही है, जहां शिवसेना के धड़े मुख्य मुकाबले में हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि शिवसेना का विभाजन कैडर को पसंद नहीं आया? कैडर आधारित पार्टियों के कार्यकर्ता दलों में बढ़ी आवाजाही से भी पसोपेश में हैं। कुछ महीने पहले तक जिसके खिलाफ वे मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे, दलीय जरूरत की वजह से उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाना प्रतिबद्ध कैडरों को पसंद नहीं आ रहा है। भले ही वे खुलकर न कह पा रहे हों, लेकिन आपसी बातचीत में वे पूछ रहे हैं कि क्या वे सिर्फ दरी और जाजम बिछाने के लिए ही हैं?

कम मतदान की एक वजह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आम मतदाताओं की अरूचि को भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राजनीति के गिरते स्तर, बयानबाजियों में गिरती भाषा का प्रयोग, राजनीति में आदर्श चरित्रों की कमी आदि से मतदाताओं के एक वर्ग का मोहभंग हो रहा है। बेशक मौजूदा राजनीतिक तंत्र आज की व्यवस्थागत मजबूरी है। लेकिन उसमें प्रेरणा के बिंदु लगातार कम हो रहे हैं। उखाड़ पछाड़ की संस्कृति राजनीतिक तंत्र का अहर्निश अंग बनती जा रही है। जनता के बुनियादी सवालों को लेकर राजनीतिक तंत्र में एक राय की कमी होती जा रही है। आज का मतदाता पहले की तुलना में तमाम तरह की सूचनाओं से कहीं ज्यादा लैस है, भले और बुरे की उसकी पहचान का आधार बढ़ा है। वैश्विक राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के लिए उसके पास संसाधन भी आज सहज उपलब्ध हैं। इस वजह से जब वह बेहतर मानव सूचकांक वाले देशों के नागरिक समाज से जब अपनी तुलना करता है तो खुद को बहुत पीछे पाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो सहूलियतें हासिल हैं, संसाधनों पर उनका जैसा अधिकार है, उसकी तुलना में जब आज का मतदाता अपनी सहूलियतों और संसाधनों की तुलना करता है तो खुद को फिसड्डी पाता है, तब उसे अपनी राजनीतिक व्यवस्था से क्षोभ होता है। बेशक वह अपने मत की ताकत से नई सरकारें चुन सकता है। लेकिन व्यवस्था को बदल नहीं पाता।

चुनावी रणभूमि से भाषा की मर्यादा, आम जनमानस के हित के मुद्दे गायब क्यों?

दीपक कुमार त्यागी

भारतीय राजनीति में गली मोहल्ले से लेकर के देश के सर्वोच्च पद तक के चुनावों में आम जनमानस के हितों को पूरा करने की बात का जिक्र हमारे सभी चुनाव लड़ने व लड़वाने वाले लोगों के द्वारा बार-बार ढिंढोरा पीट-पीट कर किया जाता है। इन चंद लोगों के लिए देशहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कहना एक बड़ा अहम चुनावी स्टंट बन गया है। लेकिन यह अलग बात है कि चुनाव जीतते ही देश व आम जनमानस के हित के लिए बड़ी-बड़ी बातें करने वाले इन अधिकांश लोगों के लिए चुनावी वायदे मात्र एक चुनावी जुमला बन करके रह जाते हैं और देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करने वाले यह लोग स्वयं पर ही सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने हित साधने के लिए लिए देश को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते हैं। वैसे देश के चुनावी रणों को देखा जाये तो हर स्तर के चुनावों में हमेशा कुछ तो लोकलुभावन वायदे व घोषणाएं हमेशा से ही रहती आयी है, जिन वायदों व घोषणाओं के झांसे में आकर के निष्पक्ष रहने वाला मतदाता किसी एक पक्ष को वोट दे कर के चुनावी समर में इनको जीत दिलवा देता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों को देखें तो पूरे चुनाव प्रचार में मेनिफेस्टो को छोड़ कर के अब तक आम जनमानस को ज्यादा कुछ वायदों का पिटारा हासिल नहीं हो पाया है। देश में अब तक के चरणों के संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव प्रचार में गिरती भाषा की मर्यादा, उटपटांग, ऊल-जलूल, कपोल-कल्पित तथ्यहीन बातों व आरोप-प्रत्यारोप का जबरदस्त बोलबाला रहा है, जो प्रगतिशील भारत व सभ्य समाज के लिए किसी भी हाल में उचित नहीं हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में देश में एक अजीबोगरीब माहौल देखने को मिल रहा है, देश के अधिकांश राजनीतिक दल जनता बीच जाते समय अपनी-अपनी पार्टी के मेनिफेस्टो की खूबियां बताने की जगह एक दूसरी पार्टी के मेनिफेस्टो की खामियों को गिनवाने में ज्यादा व्यस्त हैं। देश की चुनावी रणभूमि में अब तो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार जाति-धर्म, आरक्षण व संविधान खतरे में है, पाकिस्तान जैसे विफल देश के कपोल-कल्पित खतरे आदि के बिना सिर-पैर के मुद्दों में अटक कर रह गया है। जो स्थिति भविष्य में देश की एकता, अखंडता, सर्वांगीण विकास और विकसित भारत के सपने में एक बड़ी बाधा बन सकती है। वैसे जब कुछ माह पूर्व देश में जिस वक्त हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या धाम में दिव्य व भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह चल रहा था, तो उस वक्त अधिकांश लोगों को लगता था कि अबकी बार देश के लोकसभा के चुनावी समर में सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के बीच जातियों की सीमाएं पूरी तरह से समाप्त हो जायेगी और लोकसभा चुनावों की रणभूमि में केवल और केवल विकास के मुद्दों पर जगह-जगह विस्तार से चर्चा होगी। जाति-धर्म, आरक्षण आदि पर बोले जाने वाले तरह-तरह के चुनावी जुमले इस बार पूरी तरह से चुनाव प्रचार से ग़ायब होंगे। लेकिन अफसोस जैसे-जैसे चुनावी रणभूमि में पक्ष-विपक्ष की सेनाएं आमने-सामने आयी वैसे-वैसे ही विकास व आम जनमानस से जुड़े मुद्दे ना जाने एक-एक करके कैसे कहां गायब हो गये और उनकी जगह जाति की आड़ में लोगों को बरगलाने वाले जहरीली बयानों ने ले ली, धर्म के नाम पर आम जनमानस की भावनाओं से खेलने वाले माहौल ने ले ली। जब चुनाव कुछ आगे बढ़ा तो देश में अचानक से ही आरक्षण खतरे में व संविधान खतरे में आ गया और सभी को उसी में उलझाकर के रख दिया। वैसे देखा जाये तो इस बार के चुनावों में देश को नयी दिशा देने का दंभ भरने वाले अधिकांश लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार में आम जनमानस के हित को पीछे छोड़ करके समाज के आपसी प्यार व भाईचारे से ओतप्रोत सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने की क़सम खा ली है।

आंवला स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है

आंवला फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटैशियम, कई जरूरी विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण आदि पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना लाभदायक है। आप चाहें तो कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में आंवला का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आंवला से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बनाकर खा सकते है।

आंवला और कच्चे आम के चावल

चावल को धोकर 10-15 मिनट के लिए भिगो दें और अच्छी तरह पका लें। अब एक पैन में सरसों के दानों को तेल में भूनें, फिर इसमें चना दाल, काजू और उड़द दाल डालकर भूनकर करी पत्ता डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए कच्चे आम और आंवला मिलाएं, फिर इसमें स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं। अंत में इस मिश्रण में पके हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे गर्मागर्म परोसें।

आंवला रसम

आंवला, हल्दी पाउडर, नमक और पानी को पांच-छह सीटी तक प्रेशर कुक में पकाएं। इसके बाद एक पैन में घी गर्म करके राई, हींग, अदरक, करी पत्ता और लहसुन को भूनें, फिर इसमें हरी मिर्च, इमली का पानी, पका हुआ आंवला, टमाटर प्यूरी, पकी तुअर दाल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, चीनी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर रसम को करीब चार-पांच मिनट तक उबालें, फिर इसे उबले हुए चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।

आंवला की सब्जी

सबसे पहले गर्म तेल में हरी मिर्च, राई और जीरा डालकर भूनें, फिर इसमें कटा हुआ आंवला डालें और बीच-बीच में हिलाते हुए तीन मिनट तक पकाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, सौंफ, मिर्च पाउडर, धनियां, नमक और हींग डालकर इसे एक मिनट के लिए भूनें, फिर इसमें थोड़ा पानी और गुड़ डालकर इन्हें मिलाएं और बीच-बीच में हिलाते हुए लगभग चार मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें हरा धनिया गार्निश करके गैस बंद कर दें और इसे गर्मागर्म परोसें।

आंवले का अचार

सबसे पहले आंवले को पानी में छह मिनट के लिए बीच-बीच में हिलाते हुए पकाएं, फिर इसमें से पानी छानकर आंवलों को ठंडा होने दें। इसके बाद सौंफ और कलौंजी को एकसाथ दरदरा पीस लें, फिर इस मिश्रण में हल्दी पाउडर, मेथी दाना, हींग, सरसों का तेल, नमक और मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इसमें पके हुए आंवले डालकर अच्छी तरह मिला लें और दो घंटे के लिए अलग रख दें। इस अचार को आप परांठे के साथ खाएं।

आंवला का मुरब्बा

आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें, फिर उन्हें दो दिन तक फिटकरी के पानी में रखें। इसके बाद इसे अच्छी तरह धोकर दूसरे बर्तन में डालें, फिर सभी आंवलों को पानी और चीनी मिलाकर मध्यम आंच में पकाएं। अब इन्हें ठंडा करके एक जार में भरकर रख लें और रोजाना उसका सेवन करें।

पानी से ही सब कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेशन के लिए जरुरी हैं सब्जियों का सेवन

गर्मी का कहर पूरे जोरों पर है। देश के कई हिस्सों में पारा 50 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं, मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी बढ़ने से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन और लू लगना यानी हीट वेव का रिस्क बढ़ सकता है। यह दोनों ही आपके लिए जानलेवा हो सकता है। लू लगना और डिहाइड्रेशन के कारण आपको मांसपेशियों में ऐंठन, सूजन, बेहोशी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, पसीना, तेजी से सांस आना, दिल की धड़कान बढ़ना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। गर्मियों में पानी की कमी से बचने और शरीर को ठंडा रखने के लिए सिर्फ इन सब्जियों का सेवन करें।

अजवाइन

अजवाइन के पतों में काफी मात्रा में पानी होता है। यह गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए बेहतर ऑप्शन होता है। अजवाइन के पत्तों में 95% पानी होता है। इसे आप पीनट बटर या ह्यूमस के साथ खा सकते हैं। रसीले और स्वादिष्ट टमाटरों में लगभग 94त्न पानी होता है। इन्हें आप चाहे कच्चा सलाद या सैंडविच में खाएं या फिर पकाकर सूप बना सकते हैं।

शिमला मिर्च

रंगीन शिमला मिर्च में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लाल-पिली शिमला मिर्च में लगभग 92% पानी होता है। स्टिर-फ्राई, फजिता या किसी डिप के साथ कटी हुई शिमला मिर्च का मजा लें।

मूली और खीरा

जमीन में उगने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा

95% पानी से भरपूर होती है। मूली का स्वाद तीखा होता है इसे आप सलाद के तौर पर खा सकते हैं। वहीं खीरा का सलाद और सैंडविच खा सकते हैं। खीरे में लगभग 95% पानी होता है। इसे आप सलाद, सैंडविच या ह्यूमस के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं।

तुरई और आइसबर्ग लेट्यूस

लगभग 95% पानी वाली तुरई एक हाइड्रेटिंग सब्जी है। लेट्यूस को आप ग्रिल कर सकते हैं, सौते कर सकते हैं या इसका आप स्पिरलाइजर से नूडल्स बनाकर पास्ता की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 96% पानी होता है। इसलिए यह सलाद और रैप्स के लिए अच्छी हाइड्रेटिंग बेस बनती है।

पालक

पालक सबसे फायदेमंद सब्जियों में से एक है। हालांकि, पलाक में दूसरी सब्जियों के मुताबिक कम पानी होता है (लगभग 91%) होता है। इसके बाद यह हाइड्रेशन के लिए अच्छा विकल्प है। पालक को आप कच्चा सलाद में खा सकते हैं या फिर इसे पास्ता और ऑमलेट में डलकार खा सकते हैं।

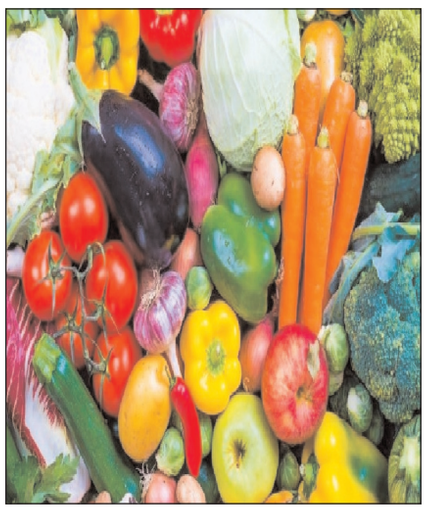

गर्मियों में वजन कम करना हुआ और भी आसान

कहा जाता है कि गर्मियों में वजन कम करना, सर्दियों के मुकाबले आसान होता है। अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करके, आसानी से वेट लॉस नहीं कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए ही वजन कम हो जाएगा। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो गर्मियों का मौसम आपके लिए बेहतर साबित होगा। वैसे तो सर्दियों में वजन करना काफी मुश्किल होता है। सर्दियों में कई कारणों से मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है। हालांकि, आप गर्मियों में वजन आसानी से कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए ही वजन कम हो जाएगा। इसके लिए आप को खूब हार्ड वर्क करना होगा। सही डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना जरुरी है। गर्मी मे फिट रहने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यह वजन कम करने के लिए भी बेहद जरुरी है। गर्मियों में आप पानी, नारियल पानी, जूस और छाछ के अलावा, वॉटर-रिच फरूट्स जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा और ककड़ी को डाइट में शामिल करें। इससे शरीर हाइड्रेट रहता और वजन भी कम होगा। गर्मियों में अक्सर हम सभी को भूख कम लगती है। जिस तरह सर्दियों में मीठा और तला-भुना खाने का मन होता है।

वहीं गर्मियों के दौरान क्रेविंग्स काफी कम हो जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक, वजन कम करने के लिए आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। गर्मियों में भारी खाना खाने से बचें और ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करें। लंच से पहले आधे घंटे पहले सलाद जरुर खाएं। इससे वजन कम करने में मदद मिलेगी। गर्मियों में वजन कम करने के लिए जरुरी है कि आप एक्सरसाइज जरुर करें। सुबह और शाम के वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप के पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो रात को सोने से पहले 1 घंटा वॉक जरुर करें। रोजाना वॉक करने से आपको फर्क महसूस होगा।

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए इन पांच तरीकों से टी ट्री ऑयल का करें इस्तेमाल

एक शोध के अनुसार, टी ट्री ऑयल त्वचा की गहराई में जाकर इन ब्लैकहेड्स को बाहर निकाल सकता है। आइए जानते हैं कि किन तरीकों से टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करके ब्लैकहेड्स दूर हो सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी और टी ट्री ऑयल का मास्क बनाकर लगाएं

ब्लैकहेड्स दूर करने के लिए सबसे पहले 5-10 मिनट के लिए अपने चेहरे को भाप दें। इसके बाद एक कटोरी में दो-तीन बूंद टी ट्री ऑयल, एक बड़ी चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक बड़ी चम्मच पानी मिलाकर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। लगभग 10-15 मिनट के लिए इस मास्क को लगा रहने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार इस मास्क का इस्तेमाल करें।

टी ट्री ऑयल वाले पानी से नहाएं

टी ट्री ऑयल वाले पानी से नहाकर भी आप ब्लैकहेड्स से राहत पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी गुनगुने पानी में एक छोटी चम्मच टी ट्री ऑयल और दो कप एप्सम सॉल्ट मिलाएं। इसके बाद इस पानी से नहाएं, फिर अपने शरीर को तौलिए से थपथपाकर सुखा लें। बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में एक या दो बार इस प्रक्रिया को अपनाएं।

टी ट्री ऑयल के स्क्रब का करें इस्तेमाल

सबसे पहले अपने चेहरे को लगभग 5-10 मिनट के लिए भाप दें। इसके बाद एक कटोरी में एक बड़ी चम्मच बारीक चिनी, एक बड़ी चम्मच जैतून का तेल और एक-दो बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर इस मिश्रण को अपने चेहरे की उन जगहों पर सर्कुलर मोशन में लगाएं, जहां ब्लैकहेड्स हैं। इसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार इस स्क्रब का इस्तेमाल करें।

टी ट्री ऑयल का मॉइश्चराइजर बनाएं

ब्लैकहेड्स से राहत दिलाने में टी ट्री ऑयल युक्त मॉइश्चराइजर भी मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद अपने मॉइश्चराइजर में टी ट्री ऑयल की एक बूंद मिलाकर इसे अपने चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं, जहां ब्लैकहेड्स हैं। आप इस प्रक्रिया को रोजाना दोहरा सकते हैं।

जोजोबा ऑयल और टी ट्री ऑयल का मिश्रण लगाएं

यह मिश्रण भी चेहरे से ब्लैकहेड्स दूर कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को कुछ मिनटों के लिए भाप दें। इसके बाद एक कटोरी में एक छोटी चम्मच जोजोबा ऑयल और एक बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर अपने चेहरे पर सर्कुलेशन मोशन में लगाएं। लगभग 5 मिनट तक मसाज करें, फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी और क्लींजर से धो लें।

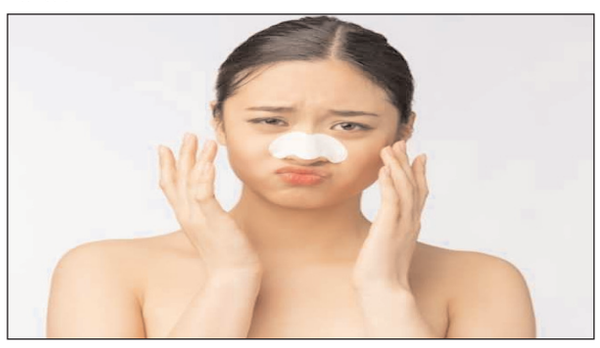

लंबे समय तक बैठे रहने वालों के लिए आईसीएमआर ने जारी किया डाईट प्लान

हम लोगों में से लगभग हर कोई अपनी वर्किंग डेस्क पर अपेक्षा से अधिक बैठता है। डेस्क पर बैठकर लंबे समय तक काम करना हमारे काम के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। समय-समय पर लोगों को डेस्क पर लंबे समय तक बैठने के जोखिम याद दिलाये जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। लंबे समय तक बैठे रहने से मोटापे, दिल की बिमारी और खराब मेटाबॉलिज्म जैसे स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे हो सकते हैं। ऐसे में उचित आहार बनाए रखना जरुरी है ताकि शरीर को जरुरी पोषक तत्व मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम किया जा सके। इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए डाइट प्लान जारी किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

आईसीएमआर ने ये डाइट चार्ट विशेष रूप से सामान्य रूप से पोषित गतिहीन पुरुषों के लिए बनाया गया है, जिनका वजन 65 किलोग्राम है और बीएमआई 18.5 और 23 के बीच है। आईसीएमआर द्वारा बताई गयी इस डाइट से गतिहीन पुरुषों को रोज की 2100 किलो कैलोरी मिलेगी। इसमें प्रोटीन से प्राप्त कैलोरी का हिस्सा 13.7% है। बता दें, मांसपेशियों के रखरखाव और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए प्रोटीन जरुरी है, जो इस डाइट से पर्याप्त किया जा सकता है।

ब्रेकफास्ट- आईसीएमआर ने ब्रेकफास्ट को सुबह 8 से 10 बजे के बीच करने की सलाह दी है। पुरुषों को अपने ब्रेकफास्ट में 90 ग्राम साबुत अनाज, 35 ग्राम उबली हुई फलियां (लाल/काली बीन्स, लोबिया या चना), 50 ग्राम प्रत्येक हरी पत्तेदार सब्जियां और मिश्रित सब्जियां, और 20 ग्राम नट्स का हिस्सा शामिल करने की सलाह दी गयी है। ये ब्रेकफास्ट शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करेगी।

लंच- आईसीएमआर ने लोगों को दोपहर 1-2 बजे के बीच खाना खाने की सलाह दी है, जिसमें 100 ग्राम साबुत अनाज अनाज, 30 ग्राम दालें या मांस और 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियों सहित 150 ग्राम सब्जियां शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, भोजन में 20 ग्राम नट्स या तेल के बीज, 150 मिलीलीटर दही या पनीर, 15 ग्राम खाना पकाने का तेल और 50 ग्राम फल शामिल होने चाहिए।

स्नैक्स- आईसीएमआर ने इसे शाम 5 बजे के लिए निर्धारित किया है। एक शाम का पेय है, जो लगभग 35 किलो कैलोरी प्रदान करना चाहिए। इसमें 50 मिलीलीटर दूध होना चाहिए, जो हल्का और पौष्टिक जलपान का विकल्प प्रदान करता है।

डिनर- आईसीएमआर ने पुरुषों को शाम 7-8 बजे के बीच डिनर करने की सलाह दी है। इसमें 80 ग्राम अनाज, 100 मिलीलीटर दही, 10 ग्राम तेल और 25 ग्राम दालें शामिल होनी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का संतुलित संयोजन पेश करती हैं। इसके अतिरिक्त, भोजन में 50 ग्राम फलों को शामिल करना चाहिए। डाइट में विटामिन, खनिज और फाइबर शामिल करना चाहिए।

आईसीएमआर ने ये डाइट चार्ट विशेष रूप से सामान्य रूप से पोषित गतिहीन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका वजन 55 किलोग्राम है और बीएमआई 18.5-23 की सीमा के भीतर है। आईसीएमआर द्वारा बताई गयी इस डाइट का लक्ष्य महिलाओं को कुल कैलोरी का लगभग 1670 किलो कैलोरी प्रदान करना है, जिसमें से 13.8त्न कैलोरी प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त होती है।

ब्रेकफास्ट- आईसीएमआर ने ब्रेकफास्ट को सुबह 8 से 10 बजे के बीच करने की सलाह दी है। इसमें 60 ग्राम भिगोया हुआ और उबला हुआ साबुत अनाज शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 30 ग्राम उबली हुई लाल या काली फलियाँ, लोबिया या छोले पौधे-आधारित प्रोटीन और फाइबर प्रदान करते हैं, जो तृप्ति और पाचन स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियाँ और 100 ग्राम मिश्रित सब्जियाँ आवश्यक विटामिन, खनिज और आहार फाइबर की कमी पूरी करेंगी। अंत में, 20 ग्राम नट्स को स्वस्थ वसा और अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करना चाहिए, जिससे भोजन का पोषण मूल्य और तृप्ति बढ़ जाएगी।

लंच- आईसीएमआर ने महिलाओं को दोपहर 1-2 बजे के बीच खाना खाने की सलाह दी है, जिसमें 80 ग्राम साबुत अनाज अनाज, 20 ग्राम दालें या मांस, और 150 ग्राम सब्जियाँ, जिसमें करी के लिए उपयुक्त 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियाँ शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसमें स्वाद के लिए 10 ग्राम मेवे या तेल के बीज, 150 मिलीलीटर दही या पनीर और 15 ग्राम खाना पकाने का तेल होना चाहिए। भोजन का समापन 50 ग्राम फलों के साथ होना चाहिए।

स्नैक्स- आईसीएमआर द्वारा शाम 5 बजे के लिए निर्धारित भोजन 3 में 50 मिलीलीटर दूध होना चाहिए, जो हल्का और पौष्टिक जलपान विकल्प प्रदान करता है।

डिनर- आईसीएमआर ने महिलाओं को शाम 7-8 बजे के बीच डिनर करने की सलाह दी है। इसमें में 60 ग्राम अनाज, 100 मिली दही, 5 ग्राम तेल और 15 ग्राम दालें शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संतुलित और पौष्टिक रात्रिभोज विकल्प के लिए इसमें 50 ग्राम फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अग्निवीर योजना को लेकर राहुल के बयान पर भड़के सिंह

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को रद्द करने की उनकी हालिया टिप्पणी के लिए तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि अग्निवीर योजना ने सैनिकों को महज मजदूर बना दिया है, जनरल सिंह (सेवानिवृत्त) ने कहा, मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें पहले सेना में काम करना चाहिए और फिर अग्निवीर योजना के बारे में कोई बयान देना चाहिए। अगर वह सेना को नहीं जानते तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भारत के सैनिकों को मजदूरों में बदलने का आरोप लगाया था और 4 जून को सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों के युवा भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं।

इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी : लालू यादव

पटना। लोकसभा चुनाव 2024 को पक्ष और विपक्ष में आरोप का दौर जारी है। रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। बिहार 7 चरण में मतदान हो रहा है और 6 फेस का मतदान हो गया और अंतिम चरण 1 जून को है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने पटना में कहा कि हमें जल्द ही नतीजे पता चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले जाएंगे। एनडीए की सरकार जाएगी और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं हैं, वह एक अवतार हैं। बिहार में हमारा गठबंधन जीत हासिल करने जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें इस बात का प्रमाण हैं कि परिवर्तन की हवा चल रही है। लालू प्रसाद लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नुक्कड़ नाटक से बिहार को क्या लाभ होगा।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अवकाश पीठ ने कहा कि यह उचित होगा, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश याचिका पर अपना फैसला दें।अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थय कारणों से उनकी एक हफ्ते की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर फैसला देने से मना कर दिया है। हालांकि, इसके लिए सीएम केजरीवाल ने 27 मई यानी सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सीएम ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुहार लगाया कि उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट सहित पीईटी-सीटी स्कैन कराने की जरूरत है और इस आधार पर उन्होंने 7 दिनों की राहत

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को

रांची। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट सोमवार को जामनत याचिका दायर कर ईडी के आरोपों को खारिज किया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। बेबुनियाद है। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भुईंहरी प्रकृति की जमीन है। उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है।

केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी को कोर्ट ने भेजा समन

नईदिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 जून को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की है। आतिशी एवं अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था जिसके विरूद्ध में प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

झारखंड को हर तरह से लूट रहे जेएमएम और कांग्रेस, मोदी बोले-

चार जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई

रांची। झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव एक जून को संताल परगना की तीन सीटों गोड्डा, दुमका व राजमहल में होना है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने सारी ताकतें झोंक दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को दुमका एयरपोर्ट पहुंचे। जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सिद्धो कान्हों, चांद भैरव जैसे वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये वीर शहीदों की धरती है। यहां पर उमड़ा जनसैलाब ये बताती कि हमारी सरकार एक बार फिर आ रही है। उन्होंने झामुमो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी पार्टियां फिर से सत्ता में आना चाहती हैं, ताकि घोटाला कर सकें। आज झारखंड को ये सभी लोग लूटने में लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के चौबीसों घंटे लूट में लगे रहने के कारण 2014 से पहले घोटाले आम थे लेकिन मोदी ने इसे रोका। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में पिछले 10 साल के मुकाबले और विकास कार्य देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो-कांग्रेस की लगातार लूट के कारण झारखंड को अब 'नकदी के पहाड़ों' के लिए जाना जाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश में चार जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी खुलेआम, बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है, ताकि उनको फिर से घोटाले करने का मौका मिल सके। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता-पिता का नाम बदल दिया। अब गरीबों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों ने तो सेना की जमीन को भी लूट लिया। आपको झारखंड को इन लोगों से मुक्ति दिलानी ही होगी। मोदी ने कहा कि भाजपा दलित, वंचित और आदिवासियों के लिए समर्पित है, समर्पण और सेवा भाव से काम करती है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुणा से ज्यादा बजट बढ़ाया। हम जनजातीय इलाके में 400

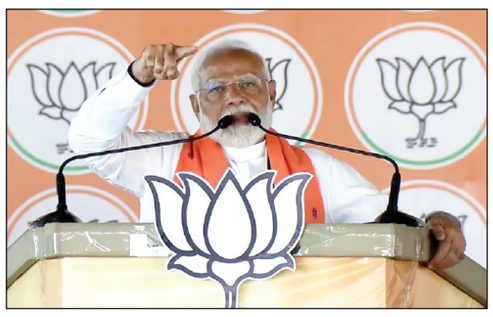

से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों के लिए खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगे की कार्ययोजना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 10 साल में हुआ है उसे और आगे बढ़ना है। मेरा लक्ष्य भारत की 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का है। उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त बिजली योजना को लागू करने की दिशा में हम शुरुआत कर चुके हैं। इसके तहत घर घर में सोलर लगाया जाएगा। इसके अलावा बिजली का बिल भी जीरो किया जाएगा।

विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोटबैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। जहां-जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार हैं- नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण! उन्होंने कहा कि अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया है।

उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की देशविरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। इनका फॉर्मूला है- घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे, उस पर हिन्दू-मुसलमान करने का आरोप लगा दो। मोदी ने कहा कि इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है कि मैं एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की लूट नहीं होने दूंगा। तो इंडी जमात को मिर्ची लग जाती है, ये कहते हैं मोदी हिन्दू-मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा! ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर लें मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट नहीं होने देगा! ये मोदी की गारंटी है।

बंगाल चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही टीएमसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पश्चिम बंगाल में अधिकतम सफलता हासिल करने पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा टीएमसी पार्टी बंगाल चुनाव में अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हम 3 थे। पश्चिम बंगाल के लोगों ने पिछली बार हमें 80 सीटें दी थीं। इस बार, भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिल रही है. पश्चिम बंगाल का चुनाव एकतरफा चल रहा है और टीएमसी बौखलाई हुई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं इन सबके बावजूद, लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं।

2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, प्रधान मंत्री ने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के फैसले के बाद न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, उनके पास एक कार्यप्रणाली है। सबसे पहले, उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया, वे सुप्रीम कोर्ट में हार गए और उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए उन्होंने चतुराई से शुरुआत की।

प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का तंज

विश्वगालीगुरू का एकमात्र सम्मान आपको प्रदान करना अनुचित नहीं होगा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आश्वस्त हैं कि उन्हें उन्हें गाली देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 24 वर्षों से उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अब वह गाली-प्रूफ बन गए हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खुद को गाली प्रूफ घोषित करके निवर्तमान प्रधान मंत्री ने आज अपने आप को एक और नयी उपाधि दी है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि दूसरों को लगातार निर्लज्जता से गाली देने वाले और बेवजह और बेपरवाह हो कर खुलेआम बदनाम करने वाले निवर्तमान प्रधान मंत्री अब 56-इंच की छाती ठोंक कर एलान कर रहे हैं कि वह 'गाली प्रूफ' हो गये हैं। रमेश ने कहा कि काश उनके भाषण भी उतने ही गाली-प्रूफ होते जितने वह खुद अपने आप को बता रहे है। भाषा के स्तर को गिराने का उन्होंने इस देश में एक नया शर्मनाक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि विश्वगालीगुरू का एकमात्र सम्मान आपको प्रदान करना अनुचित नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी एक ऐसे प्रधान मंत्री को जिनके जैसी भाषा का प्रयोग करने से बच्चों को रोका जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब बच्चों को कहा जाएगा- बच्चों, कुछ भी करना पर मोदी जी जैसी भाषा का इस्तेमाल मत करना।

पीएम मोदी एएनआई से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इतना हताश है कि गाली-गलौज करना विपक्ष का स्वभाव बन गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक मोदी की बात है तो पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद मैं गाली प्रूफ बन गया हूं। मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा?

शिवसेना-यूबीटी का केंद्र सरकार पर वार

मुंबई। शिवसेना- यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को 4जी और 5जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी। इससे उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान हुआ है।

सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 21 मई को एक जारी किया गया एक पत्र साझा किया है। यह पत्र संचार मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किया गया था। इसमें एमटीएनएल और बीएसएनएल की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बात लिखी गई थी। पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को उबारने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में दोनों कंपनियों की भूमि और जमीनों का मुद्रीकरण भी शामिल है। पत्र में आगे लिखा गया है कि देशभर में बीएसएनएल की संपत्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल की जमीनें मौजूद हैं, जिनमें कुछ जमीनें प्रमुख जगहों पर स्थित हैं। पत्र में आगे लिखा है कि इन संपत्तियों को सरकारी विभागों को सीधे बिक्री के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

4 भारतीय खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप खेलने मैदान पर उतरेंगे

नईदिल्ली। भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएस जा चुके हैं। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ही पीछे रहे हैं।रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अमेरिका पहुँच गई है। भारतीय टीम का अभियान वॉर्म अप मैच से शुरू होने वाला है। इसके बाद मुख्य मैचों की तरफ मामला जाएगा।

टीम इंडिया में चार खिलाड़ी रिजर्व रखे गए हैं। कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिनको अभी तक किसी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिल पाया है। उनके लिए यह सुनहरा अवसर माना जा सकता है। इन खिलाड़ियों की तरफ नजरें रहेंगी।

संजू सैमसन:घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक संजू ने अपने प्रदर्शन से दिल जीता है। इस बार भी आईपीएल में सैमसन ने धमाका किया था। उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए थे और उनकी टीम प्लेऑफ़ में भी गई थी। सैमसन पहली बार वर्ल्ड कप में खेलेंगे, इसे लेकर वह उत्साहित जरुर होंगे।

यशस्वी जायसवाल: इस युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रभावित किया था। आईपीएल में भी वह शतक जमाने में सफल रहे थे। जायसवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनका पहला वर्ल्ड कप होगा। उनका खेल देखने लायक रहेगा।

शिवम दुबे: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए धमाका करने वाले शिवम दुबे ने अपने बल्ले से स्पिनरों की जमकर पिटाई की है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी करने की क्षमता भी विकसित की है। इसे देखते हुए वह टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किये गए हैं।

युजवेंद्र चहल: इस लेग स्पिनर को टीम इंडिया में पहले भी शामिल किया गया है लेकिन प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में इस बार उनको खेलते हुए देखा जा सकता है। चहल की स्पिन गेंदबाजी ने आईपीएल में बड़ा धमाका करने में सफलता पाई है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 220 अंक टूटा निफ्टी 22,888 पर बंद

नईदिल्ली। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के साथ बंद हुआ। लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने आज मुनाफावसूली की जिसके चलते बाजार आज गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज बढ़त के साथ 75,585.40 अंक पर खुला। हालांकि, सेंसेक्स दिन भर हरे और लाल निशान के बीच झूलता रहा और अंत में 0.29 प्रतिशत या 220.05 अंक की गिरावट लेकर 75,170.45 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी -50 भी पॉजिटिव शुरुआत के बावजूद 44.30 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 22,888.15 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति के शेयर गिरावट में रहे।

31 मई तक पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

नईदिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। आयकर नियमों के अनुसार, यदि परमानेंट अकॉउंट नंबर बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारिती तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।'' विभाग ने कहा, '' एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है।

अदाणी ग्रुप की यूपीआई और ई-कॉमर्स में एंट्री की योजना!

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप यूपीआई पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेक्टर में अपने पैर पसारने की योजना बना रहा है। बता दें कि गौतम अदाणी ग्रुप पब्लिक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क पर काम करने को लेकर लाइसेंस अप्लाई करने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं अदाणी ग्रुप को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए भी बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है। द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह कदम डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में विविधता लाने के समूह के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि अरबपति गौतम अदाणी ग्रुप भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) नेटवर्क में एंट्री करके अपने डिजिटल कारोबार का विस्तार करना चाहता है। इतना ही नहीं अदाणी ग्रुप सरकारी प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिये ऑनलाइन शॉपिंग की पेशकश करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया में है।

आरबीआई ने दो बड़े बैंकों के खिलाफ की कार्रवाई

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई की है। आप है कि येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक ने येस बैंक पर 91 लख रुपए और आईसीआईसीआई बैंक पर एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही बैंक कई दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। आरबीआई के दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं हो रहा था। कस्टमर सर्विस और इंटरनल ऑफिस अकाउंट से संबंधित नियमों का उल्लंघन येस बैंक द्वारा किया जा रहा था। आरबीआई का कहना है कि कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर्याप्त बैलेंस न होने पर कई अकाउंट से येस बैंक ने चार्ज वसूला था।

बच्चों में खर्च के साथ बचत की डालें आदत

नारायण कृष्णमूर्ति

बच्चों को वित्तीय साक्षरता के कौशल से लैस करना उनके बेहतर भविष्य के लिए निवेश की तरह है। हर माता-पिता को यह करना चाहिए। बच्चों में पैसे खर्च करने के साथ बजट बनाने और बचत करने की समझ पैदा करनी चाहिए। इससे हम उन्हें भविष्य में वित्तीय रूप से मजबूत बना सकते हैं।

बच्चों को पैसों के प्रति गलत धारणा से बचाने और उन्हें जागरूक बनाने की शुरुआत जल्द करनी चाहिए। इससे बच्चों को उस धारणा से बाहर आने में मदद मिलती है कि पैसे सीधे एटीएम से आता है। शिखा दिल खोलकर बात करने वाली बच्ची निकली और वह मुझसे यह समझना चाहती है कि पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए। उसने जब पैसे खर्च करने और सही तरीके से खर्च करने के अंतर का जिक्र किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बच्चे अक्सर खर्च करने से खुश होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, उन्हें पैसे बचाने या कमाने के बारे में बहुत कम समझ होती है। इसलिए, मैंने उससे पूछा कि सही तरीके से खर्च करने का क्या मतलब है। उसने बताया कि उसे अपने जन्मदिन पर दादा-दादी से पैसा मिला था, जो एक हफ्ते में खत्म हो गया। 350 रुपये के एक पेंसिल बॉक्स को छोड़कर उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने 1,000 रुपये का क्या किया।

हमारी चर्चा इस बात से शुरू हुई कि एक नोटबुक रखना कितना जरूरी है, जिसमें बताया जाए कि आप कहां-कहां पैसे खर्च कर रहे हैं। शिखा ने नोटपैड पर इसे लिख लिया। मैंने पूछा कि क्या उसे पता है कि अभी उसने जो आइसक्रीम खाई थी, उसकी कीमत कितनी थी? उसने कहा, 20 रुपये। उसे स्कूल फीस, आर्ट क्लास फीस, घर पर

नौकरानी और कार की सफाई करने वाले को दिए जाने वाले पैसे की भी जानकारी थी।

ये सभी छोटी-छोटी नियमित गतिविधियां हैं, जो किसी भी घर का हिस्सा होती हैं। बच्चों को इनके बारे में जानकारी देना अच्छा विचार है। 7-8 साल की उम्र से बच्चों पर भरोसा किया जा सकता है कि वे स्कूल कैंटीन या स्टेशनरी की दुकान पर चीजें खरीदने के लिए छोटी रकम खर्च करें। इस तरह, वे उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी की सराहना करेंगे। उन्हें यह एहसास भी कराएं कि नुकसान का क्या मतलब है। बच्चे जब 13-14 साल के हो जाएं तो उन्हें अपना बजट खुद बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैंक खाता खोलने और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कम सीमा वाले डेबिट कार्ड भी दें। इससे उन्हें कुछ वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी।

वित्तीय स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए। यानी बच्चों में खर्च करने के साथ पैसे बचाने की आदत डालें। उन्हें तोल-मोल करने में सक्षम बनाएं। याद रखें, अब तक वे केवल खर्च करने के लिए पैसे देख रहे थे। अब वे इसे अलग नजरिये से देखेंगे, जिसमें पैसे कमाना भी शामिल है। उन्हें अपनी हर इच्छा के लिए भुगतान करने के बजाय अपनी कमाई से अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। याद रखें कि वित्तीय साक्षरता सिखाना एक सतत प्रक्रिया है, जो बच्चों के बड़े होने और उनकी समझ के गहरा होने के साथ विकसित होती है। इन रणनीतियों को लागू करके, हम अपने बच्चों को वित्तीय रूप से सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के लिए एक ठोस आधार देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए, शुरुआत करें और उनके बड़े होने पर भी इसे जारी रखें।

बच्चे जब 16-17 साल के हो जाते हैं तो उन्हें निवेश पर परिवार के फैसलों में भी शामिल किया जा सकता है। इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि आपकी कमाई कैसे होती है और आप इसका क्या करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण खर्चों पर पारिवारिक चर्चाओं का हिस्सा बनाएं। जैसे छुट्टियां बिताना, कार खरीदना आदि। यह बच्चों के शिक्षा के खर्चों के बारे में जानने का भी अच्छा समय है कि पैसे कमाने व जीवन जीने के लिए किसी पेशे या करियर के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इस चरण में आप उनकी ओर से तब निवेश शुरू कर सकते हैं, जब वे 18 वर्ष से कम उम्र के हों और कमाना शुरू करें।

सारा बस्तर निर्दोषों की हत्या के खिलाफ लामबंद

सरकार मुठभेड़ की जांच से डर क्यों रही - दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सारा बस्तर फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ लामबंद है, लोग बस्तर बंद कर अपना आक्रोश जता रहे है। लेकिन अत्याचारी भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को जांच से क्या परहेज है? सरकार इस मामले की जांच से घबरा क्यों रही है? पांच माह में ही साय सरकार अत्याचारी और क्रूर बन गयी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी मारे जा रहे। आदिवासी को न्याय के लिये आंदोलन करना पड़ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गृहमंत्री विजय शर्मा को आमंत्रण दिया कि वे हमारे साथ ग्रामीणों से मिलने पीडिया चले उन्हें सच्चाई पता चल जायेगी वहां क्या हुआ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीडिया में हुये मुठभेड़ में और इसके पहले कांकेर के कोयलीबेड़ा में हुये मुठभेड़ में कुछ निर्दोष लोगो की हत्यायें हुई थी। कांग्रेस ने इस मामले की हाईकोर्ट के न्यायाधीश की देख-रेख में जांच की मांग किया था। आज इसी मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस इस बंद का समर्थन किया है। पीडिया और कोयलीबेड़ा दोनों मुठभेड़ की जांच होनी चाहिये। सरकार निर्दोष लोगों की हत्याओं पर विराम लगाये जो लोग दोषी है उन पर कार्यवाही करें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी मुठभेड़ पर अपनी ओर से सवाल खड़ा नहीं किया है। गांव वालों ने सवाल खड़ा किया हमने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी तथ्यों को सही पाई। सरकार इसकी हाईकोर्ट के जज से जांच करवा लें। सरकार को यह सोच बदलना होगा कि हर आदिवासी नक्सली होता है। आदिवासी पीड़ित है उसकी सुरक्षा होनी चाहिये, हमने गृहमंत्री को पत्र लिखकर कहा है विश्वास विकास सुरक्षा की पूर्ववर्ती सरकार की नीति को जारी रखा जाये। उसी नीति से बस्तर में नक्सलवाद 80 प्रतिशत तक कम हुआ था। पीडिया में मारे गये 6 लोगों का आपराधिक रिकार्ड गृहमंत्री जारी कर रहे, शेष लोग क्यों मारे गये सरकार यह बताये?

राज्य में शातिर शूटरों की आमद चिंताजनक- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में अंतर्राज्यीय शूटरों की आमद चिंताजनक है। यह राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण है। अपराधियों में पुलिस का धौंस समाप्त हो गयी है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी पांच महिना नहीं हुये है प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये है अपराधी बेलगाम हो चुके है सरेआम लोगो की हत्याएं की जा रही है गोलियां चल रही है।

बैज साय सरकार का शुक्रिया अदा करें, बस्तर हो रहा है भय मुक्त

जगदलपुर/रायपुर। वनमंत्री केदार कश्यप ने दीपक बैज के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केदार कश्यप ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज राग अलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी लगातार भाजपा नेताओं को धमकी देते रहे हैं।

उन्होंने कहा चाहे नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या पखांजूर क्षेत्र हो, हमारे भाजपा जनप्रतिनिधियों को जान से मारने धमकी दे रहे हैं और तो और नारायणपुर की घटना जिसमें विक्रम बैस की मौत हुई है। इसके जो दोषी है वे कांग्रेसी कार्यकर्ता रह चुके हैं। हस्दू के अध्यक्ष रह चुके हैं। दीपक बैज पखांजूर की घटना को ना भूले। स्व. असीम राय जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष थे उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है।

ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार जांच पड़ताल कर रही है जो ऐसे जो दोषी लोग हैं उनको जेल का रास्ता दिखा रही है। कानून से कोई बच नहीं सकता। दीपक बैज आपको शुक्रियादा करना चाहिए कि विष्णुदेव साय की सरकार हमारे पूरे क्षेत्र को भय मुक्त बना रही है।

बाबू भैया की कलम से

सोशल मीडियाः ईश्वर के निर्देश पर भारत में हुआ 'कल्कि अवतार'

जैसे जैसे 4 जून मतगणना का समय नजदीक आ रहा है,सोशल मीडिया में पोस्ट की भीड़ तेजी से बढ़ती ही जा रही है। एक वर्ग भाजपा की कही भी बात नहीं कर रहे बल्कि नरेंद्र मोदी व उनके गठबंधन को 400 से ऊपर पहुंच रहा है। वह भी बड़ी ही सफलता के साथ इस बार 400 निश्चित पार का टॉरगेट पूरा होता दिखा रहे हैं। मानों राजनैतिक दल बेमानी हो गए हो और यह संकेत दे रहे हैं मानों व्यक्तिवाद का युग आ गया हो,या आ रहा हो। इस वर्ग की सोच को कोई दोष नहीं दे सकता क्योंकि देश में हवा ही इस तरह की चलाई गई है कि मोदी है तो मुमकिन है अन्यथा कुछ नहीं है। इंडिया और मोदी समर्थकों का अपना अपना एजेंडा तय है। प्रोपेगेंडा में हर तरफ 2024 के आम चुनाव में सिर्फ मोदी ही मोदी मौजूद हैं उसके सिवाय कोई नहीं। यह सच भी है कि यदि मोदी को कम कर दिया जाए तो भाजपा की वर्तमान राजनीति में कोई दूसरा तैयार खड़ा है, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। यही कारण है कि भाजपा की केंद्र की सरकार अब मोदी की सरकार में परिवर्तित हो चुकी है। दूसरा नेतृत्व भाजपा में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल ने इस भाजपाई तूफान के बीच तुक्का छोड़ दिया कि मोदी चुनाव जीतने के बाद अमित शाह को प्रधान मंत्री बनाएंगें। उधर जरूर किसी सोची समझी रणनीति की तहत ही राहुल गांधी ने यही बात आगे बढ़ाई। कहा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगें। सरकार में दूसरे नम्बर के नेता अमित शाह को इसके पीछे की राजनीति समझ में आ गई। उन्होंने झट से बयान दे डाला कि नरेंद्र भाई 2029 तक प्रधान मंत्री का अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगें। वैसे भी इस दल के नेताओं के बयान में सत्ता 2047 तक छोड़ने की मंशा दिखाई नहीं देती। तभी तो कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देंगें। 75साल में रिटायरमेंट की बात अब कोई नहीं कर रहा।

इस बार चुनाव कुछ अलग ही स्वरूप में हो रहे हैं। बयानवीरों का मुद्दों से ज्यादा ध्यान शब्दों व घटनाओं पर केंद्रित हो गया है। 'मंगलसूत्र, 'भैंस खोलने', 'मुजरा', 'जायदाद लूटकर बांट देने', 'आरक्षण लूट कर दूसरो को बांट देने', 'ईश्वर के अवतार' जैसी बहुत सी नई नई बातें सामने आ रहीं है,जो ना कभी देखी ना सुनी। ये सब भी राजनीति के मुद्दे बन सकते हैं ,वो भी प्रधान मंत्री के द्वारा बनाए जाएंगे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये वर्तमान राजनीति में हो रहा है। सोशल मीडिया तो एक नहीं कई कदम आगे भाग रही है। यहां भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस को भी राजनीति में कुदा दिया गया है। उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से मोदी जी को अवतार व महान बताने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि 'तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा,जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा उसकी प्रशंसा व प्रसिद्धि सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा' यह पोस्ट बकायदा प्रमाण सहित लिखी गई है। बताया गया हैं कि यह सेंचुरी 1- का 50 वां सूत्र के अनुसार लिखा गया है। अब सोचिये किसको ये पोस्ट करने वाले ऐसा अद्भुत नेता बता रहे हैं। और भी बहुत सी भविष्य वाणी नास्त्रेदमस के नाम पर प्रदर्शित कर इशारा प्रधानमंत्री की ओर किया जा रहा है। समर्थकों ने सोशल मीडिया में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।सोशल मीडिया के अनुसार अब तो दुमका झारखंडमें प्रधानमंत्री ने नई बहस छेड दी है। उन्होंने कहा है की रविवार की सासाहिक छुट्टी हिंदुओं से जुड़ी नहीं है। यह ईसाई समाज से जुड़ी है। इसका क्या मायने निकाला जाए ,यह अभी तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के बयानवीरों के अनुसार भगवान विष्णु से जुड़े बृहस्पतिवार को यह सासाहिक छुट्टी होनी चाहिए यह भी कि ऐसी भविष्यवाणी 500 साल पहले ही नास्त्रेदमस ने कर दी थी। यानी अब संकेत दिया जा रहा है कि भारत में ईश्वर के निर्देश पर काम करने वाला अवतार पैदा हो चुका है,जो देश दुनिया का उद्धार करने, 2047 तक दुनिया बदलने की ताकत बनेगा। बुद्धिजीवी यह सब देख कर कहते हैं कि जो माहौल बनाया जा रहा है ,उससे तो मान लेना चाहिए कि भारतवर्ष में होने वाला 'कल्कि अवतार' अवतरित हो चुका है जो ईश्वर के निर्देश पर काम कर रहा है।

निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है मतगणना, प्रेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण - रीना बाबासाहेब

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना प्रेक्षक (काउंटिंग ऑब्जर्वर) की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण में कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को मतगणना के सभी पहलुओं की बारीक जानकारी होनी चाहिए। मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए मतगणना प्रेक्षक को निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम

देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी निभाएंगे मतगणना प्रेक्षक की भूमिका

निर्वाचन-2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल, विनय अग्रवाल और रुपेश कुमार वर्मा ने मतगणना स्थल पर प्रेक्षक की भूमिका, ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना हॉल में कितने टेबल लगाए जाने हैं, टेबल किस प्रकार लगाए जाने हैं, प्रत्याशी, उनके अधिकृत प्रतिनिधि और मतगणना अभिकर्ता कितने होंगे तथा किन स्थानों पर बैठेंगे, वीवीपैट की गणना के लिए कौन सा टेबल निर्धारित किया जाए, डाक मतपत्रों की गणना कहाँ हो, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्त राज्य के अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्थल पर मास्टर ट्रेनर श्री रुपेश कुमार वर्मा ने प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का संचालन भी अधिकारियों के समक्ष किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे

श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, आदेश जारी

रायपुर। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है।

आजादी के 75 वर्षों बाद गरियाबंद के छिंदौला गांव में पहुंची बिजली, गांव वालों ने सीएम साय को भेजा न्यौता

मुख्यमंत्री बोले - जनता खुश है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार सुशासन को ध्येय मानकर लोगों के हित के काम करने में जोर-शोर से जुटी है। इसका परिणाम है कि सरकार के काम का सकारात्मक असर भी दिख रहा है। जिसका उदाहरण है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का छिंदौला गांव। जहाँ रहने वाली विशेष पिछड़ी कमार जनजाति ने आजादी के 75 वर्षों के बाद बिजली की रौशनी के दर्शन किये।

गांव के कमार बस्ती में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने न केवल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया वरन् मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने गांव आने का न्यौता भी दिया है। इस विषय पर साय ने कहा है कि - ऐसी खबरें हमारी सरकार के अच्छे कार्यों का प्रमाण है, जिससे आत्मिक संतोष मिलता है। सुशासन को ध्येय मानकर कार्य कर रही हमारी सरकार ने गरियाबंद जिले के छिंदौला गांव में जनमन योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया है। जिससे कि आजादी के 75 वर्षों बाद गांव के रहवासियों विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों को रौशनी देखने को मिली है। ग्रामीण खुश हैं और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। गौरतलब है कि मैनपुर तहसील मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दबनई के आश्रित ग्राम छिंदौला में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोग रहते हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

संथाल में सीएम साय करेंगे चुनावी सभा को संबोधित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय झारखंड के संथाल परगना में 29 मई को बरहेट, पाडरकोला, शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम साय विशेष विमान से रायपुर से देवघर के लिये रवाना होंगे। उसके उपरांत बरहेट के गोपालडीह के फुटबाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत पाडरकोला के फुटबाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने के पश्चात वापस राजधानी रायपुर के लिये रवाना होंगे। मुख्यमंत्री साय लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिये 1 जून को हो रहे मतदान के पूर्व इन चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके पूर्व भी सीएम साय खुंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व जमशेदपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं।

दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच की सुविधा

रायपुर । रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की ग्रीष्मकालीन समय में बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु गाड़ी संख्या 22867 एवं 22868 दुर्ग निजामुद्दीन- दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच की सुविधा 28 एवं 31 मई और 4 एवं 7 जूनको अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

15 नक्सलियों की गिरफ्तारी पर साय ने दी सुरक्षाबलों को बधाई

रायपुर। दंतेवाड़ा जिले के गिरसापारा की पहाड़ियों में सुरक्षाबल के जवानों ने पंद्रह नक्सलियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए नक्सलियों में सात महिला और आठ पुरुष नक्सली हैं। जिसमें से एक नक्सली बीजापुर और चौदह नक्सली नारायणपुर जिले के हैं। सुरक्षाबलों को मिली इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। श्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ङ्ग पर लिखा है कि - सुरक्षाबलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दंतेवाड़ा के गिरसापारा की दूरस्थ पहाड़ियों से 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलमुक्त बस्तर की दिशा में यह एक और कदम है।

नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, जो उसके खात्मे तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। सुरक्षाबलों द्वारा बस्तर संभाग में रोज नक्सलियों को मारने, गिरफ्तार किये जाने या आत्मसमर्पण करवाने में सफलता मिल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से आशातीत सफलता मिल रही है>

पाक से वोट अपील करवाने वाली कांग्रेस भाजपा को ना सिखाए

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने स्वातंर्त्यवीर सावरकर को लेकर कांग्रेस खेमे की ओर से सामने आई एक टिप्पणी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान से कांग्रेस के लिए वोट की अपील कराने वाले कांग्रेसी की अब यह राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है कि वे वीर सावरकर को लेकर बार-बार अपनी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करें। भाजपा को यह न सिखाएँ कि भाजपा किनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करे? अपने राष्ट्र के लिए तिल-तिलकर अहना समूचा जीवन अमानवीय यंत्रणाओं के साथ समर्पित कर देने वाले महापुरुषों का स्मरण हमें अपने बलिदानी-इतिहास के गौरव के साथ जोड़ता है। श्रीवास्तव ने कहा कि स्वातंर्त्यवीर सावरकर की पावन जयंती की बेला पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देते हुए किए गए ट्वीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करके एक खानदान की चाटुकारिता करके अपनी वैचारिक दरिद्रता का ही प्रदर्शन किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हैजो हमेशा भारत-विरोधी दुश्मन देशों व लोगों से छिप-छिपकर मिलती और बातें करती रही है, पाकिस्तान से अपने लिए वोट की अपील करवाती है.

ई वे बिल में छूट की समाप्ति व्यापारियों पर अत्याचार

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा ई वे बिल सिस्टम छूट को समाप्त किये जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सरकार का व्यापारियों पर अत्याचार है। जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है सरकार उद्योग व्यापार को चौपट करने वाला निर्णय ले रही है। जिन व्यापारियों उद्योगपतियों के दिये जाने वाले टैक्स के पैसे से सरकार विकास और राहत के काम करती है। उन्हीं व्यापारियों को परेशान किया जाना गलत है? पांच महिने में लगातार व्यापारियों के यहां सरकार ने जीएसटी के छापे मारी करवाया। अब सरकार उनको परेशान करने ई वे बिल में छूट को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस सरकार के इस कदम का विरोध करती है। शुक्ला ने कहा कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया इस दौरान कांग्रेस ने जीएसटी के कई स्लैब और इसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे और पूरे देश में व्यापारी वर्ग भी इसके खिलाफ रहे हैं। जीएसटी के विषय पर अब तक 3000 से अधिक सुधार किया गया है। उसके बावजूद जीएसटी की समस्या निरंतर बनी हुई है। भाजपा नेता जीएसटी को लेकर अपनी केंद्र सरकार की नाकामी को ढकने के लिए अब सीधा-सीधा व्यापारी को ही टैक्स चोर कह रहे है।

बेमेतरा ब्लास्टः किसको संरक्षण देने अब तक नहीं हुई एफआईआर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के ग्राम पिरदा स्थित फैक्टरी में ब्लास्ट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि बेमेतरा ब्लास्ट, किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनेहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है? सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास? जवाब तो देना होगा। बघेल ने पांच सवाल किया है। साथ ही उसका जवाब भी मांगा है। उन्होंने लिखा कि इस दिल दहलाने वाली घटना में मृतकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शरीर के अंगों को पॉलीथिन में जमा करके डीएनए जाँच के लिए भेजा गया है, लेकिन इतने भयावह हादसे के बाद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 48 घंटे बाद भी घटना की अब तक एफआईआर क्यों नहीं? क्या प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा है कि घटना वाले दिन कितने मजदूर वहां काम पर गए थे? अब तक कितने मजदूर लापता हैं क्योंकि प्रशासन के 8 लोगों के दावे को तो ग्रामीण नकार रहे हैं। क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है? जाँच में विस्फोटक सामग्री की क्या मात्रा दर्ज की जाएगी? प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवज़ा देने की घोषणा की है उसे तो लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है।

सचिव श्रीमती आबिदी ने पुलिस, रेलवे, बीएसएनएल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली

चाईल्ड हेल्पलाईन को प्रभावी बनाने पुलिस के साथ इंट्रीग्रेशन

रायपुर। बच्चों एवं महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 घंटे आपातकालीन सेवा के रूप में बच्चों के लिए चाईल्ड हेल्पलाईन सी.एच.एल-1098 एवं महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाईन डब्ल्यू.एच.एल-181 संचालित है। उक्त हेल्पलाईन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा संचालित ई.आर.एस.एस-112 के साथ इंटीग्रेशन किया जा रहा है। हेल्पलाईन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने सी-डैक तिरूअनंतपुरम, पुलिस विभाग की ई.आर.एस.एस-112 की टीम, बीएसएनएल, रेलवे एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को हेल्पलाईन को बच्चों एवं महिलाओं की त्वरित मदद के लिए प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती तुलिका प्रजापति भी मौजूद थी।

सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के परिपालन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में सभी 33 जिलों में चाईल्ड हेल्पलाईन संचालन हेतु हार्डवेयर लगाया जा चुका है। 32 जिलों में चाईल्ड हेल्पलाईन का डब्ल्यू.सी.डी. कंट्रोल रूम से इंटीग्रेशन कर संचालन प्रारंभ हो चुका है। इंटीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सी-डैक एवं बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। राज्य के 27 जिलों के वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर) में महिला हेल्पलाईन यूनिट की स्थापना एवं इंटीग्रेशन कर संचालन किया जा रहा है। सचिव, महिला एवं बाल विकास ने रेलवे रायपुर एवं बिलासपुर से आए अधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में रायपुर एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन के उपयुक्त स्थान पर चाईल्ड हेल्पलाईन का संचालन किया जाए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित आधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को स्वयं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन

रायपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर, आईसीएमएआई-रायपुर चैप्टर लाइफ केयर ब्लड सेंटर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन 28 मई को आईसीएमएआई-रायपुर चैप्टर, आर-7 सेक्टर-2, अवंती विहार, रायपुर मे किया गया। जिसमें सीएमए के विद्यार्थी, सीएमए क्वॉलिफेड प्रोफेशनल एवं अन्य समिति के सदस्यों द्वारा रक्त दान कर अपना सहयोग दिया शिविर में मुख्य अतिथि के रुप मे सीएमए अरिदम गोस्वामी रिजनल वाइस चेयरमैन उपस्थित रहे एवं समस्त रक्त दान दाताओं को धन्यवाद के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किया चर्चा के दौरान रक्त दान के लाभ की भी जानकारी दी गई की प्रत्येक दान अधिकतम तीन जीवन बचा सकता है। आपका दान सुनिश्चित करता है कि सर्जरी, आपात स्थिति और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए रक्त उपलब्ध हो रक्तदान करने से दानकर्ता की भी हानिकारक लौह भंडार कम करता है साथ ही कैंसर का खतरा को घटाता है और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रक्त दान प्रत्येक व्यक्ति जो 18-65 वर्ष की आयु का हो और वजन कम से कम 50 किलो हो रक्त दान कर सकता है उपरोक्त सभी जानकारी सीएमए सौरभ दास सेक्रेटरी रायपुर चैप्टर द्वारा दी गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.